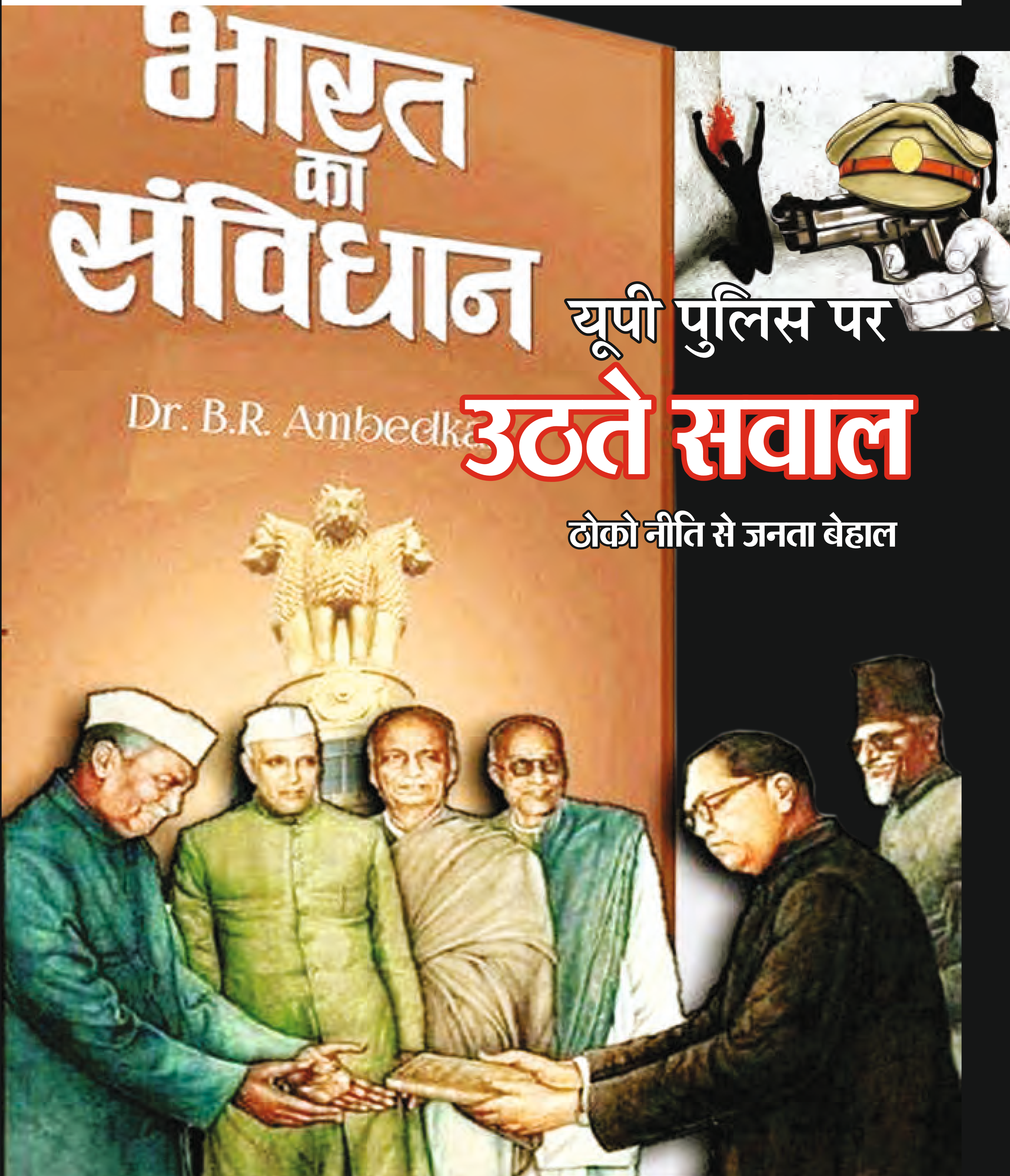
TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 1, संयुक्तांक : 04-05 आजमगढ़ • अक्टूबर-नवम्बर 2021 • मूल्य : ₹30



यूपी पुलिस पर उठते सवाल

ठोको नीति से जनता बेहाल

संपादकीय



कोरोना संकट के दौरान देश में तमाम गतिविधियाँ बंद रही। कई महीनों की बंदी के साथ लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया। स्कूल और कालेज भी बंद रहे। जबकि एम्स और यूनिसेफ जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वैज्ञानिक आधार पर 15 वर्ष से छोटे बच्चों को कोरोना की वजह से किसी भी तरह की गंभीर खतरे की आशंका नही है। दुनिया भर में स्कूल सिर्फ 4 या 5 महीने ही बंद रहे स्वीडन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने स्कूल एक भी दिन बंद नही रहे, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल 18 महीनों तक बंद रहे, स्कूलों की बंदी के दौरान मैदान में शिक्षा से जुड़े नये कारपोरेट खिलाडियों बॉयजू और वेदान्तु जैसे ऑनलाइन शिक्षा में आगे आये। आँकड़े बताते हैं कि 10 करोड़ बच्चों में में से सिर्फ 4 करोड़ के पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के साधन हैं। देश के 28 करोड़ बच्चों में से 7 करोड़ बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर पा रहे है। 21 करोड़ बच्चे शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं। कोरोना को अवसर मानते हुए, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सरकारी स्कूलों को बंद रखकर भविष्य में कुछ खास कारपोरेट घरानों को सौपने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। देश में अब स्कूली शिक्षा को बायजू और वेदान्तु जैसे ऑनलाइन शिक्षा के मास्टर तय करेंगें।

सितम्बर और अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हुई, कई मौतें ने देश वासियों को हिलाकर रख दिया, पुलिस कस्टडी में हुई मौतों से पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे है गोरखपुर में मनीष गुप्ता, आगरा में अरुण वाल्मीकि और कासगंज में अल्ताफ अहमद की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। कासगंज की घटना तो विश्वास से परे है कि महज दो फीट की ऊंचाई से साढ़े पांच फीट लम्बा युवक लटक कर आत्महत्या कैसे कर सकता है? उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला भी सुर्खियों में रहा। जहाँ 4 किसानों की लक्जरी गाड़ियों से कुचलकर कर हत्या कर दी गयी। ये किसान अपने अधिकारों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की गयी लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, फिर भी अभियुक्तों की सरकार में गहरी पैठ होने के कारण, घटना के पीछे बैठे मठाधीशों के खिलाफ कार्यवाही नही की गई। संविधान के रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट के कड़े रवैये के बाद इनके खिलाफ आधी अधूरी कार्यवाही की गई। नवंबर महीने में संविधान दिवस है। 26 नवंबर को देश संविधान दिवस मनायेंगा, संविधान दिवस की शुभकामनाओं के साथ बसावन इंडिया का नया अंक आप लोगों के बीच है।

नरेन्द्र

TITLE CODE : UPHIN49731
आजमगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह- अक्टूबर- नवम्बर
सन् - 2021 ▪ वर्ष - 1 ▪ अंक - 4-5

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार
डॉ. श्रद्धा, परिभाषा
बिनिका दुर्गम
कमलेश यादव
मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - अतुल कुमार
लखनऊ - देशराज (एडवोकेट)
बिहार - आलोक नाथ 'भंटू'
छतीसगढ़ - गणेश सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादूर
महाराष्ट्र - आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कानपुर - सुनील कुमार सुनील
कुशीनगर - कोमल प्रसाद

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आऊट
प्रभाकर प्रिंट हाऊस
+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़
उत्तरप्रदेश पिन - 276 001
संपर्क : +91 9453171770
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 945317170

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटिंर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व तथागत शहीद द्वार, सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन - 276 001 से प्रकाशित।

इस अंक की झलकियां

यूपी पुलिस पर उठते सवाल
ठोको नीति से जनता बेहाल



▪ **डॉ. गजेन्द्र सिंह यादव**
एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहबाद

गोरखपुर में युवा व्यवसायी मनीष गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत फिर आगरा में पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि नामक शख्स की मौत, वो भी 20 दिनों के भीतर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिह्न उठा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही है, झांसी में पुष्पेन्द्र यादव की हत्या हो जौनपुर में पुजारी यादव की हत्या, या फिर लखनऊ में नीरज तिवारी की हत्या। नोएडा में तो एक शादी समारोह से लौट रहे युवक जितेन्द्र कुमार यादव को पुलिसवालो ने गोली मार कर अपराधी करार दे दिया था वो संयोग वश बच गया लेकिन अब बेचारा अपाहिजों (तकनीति भाषा में दिव्यांग) का जीवन जीने को विवश है।

प्रदेश में 2017 से पुलिस मनमाने तरीके से बेलगाम होकर काम कर रही है। अब लोग अपराधियों की जगह पुलिस से भय खाने लगे है।

पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार मुठभेड़ों के समर्थन में ये कहा जाता रहा है कि जो भी लोग मारे गए हैं वह गम्भीर अपराधी थे और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए मुठभेड़ करनी पड़ी जिनमें ये सभी मारे गए।

जबकि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एक माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर एक हलफनामें से पता चला है कि वर्ष 2017 से 2018 तक एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 50 मौतें एनकाउंटर में हुई थीं। इन मौतों में 14 आरोपी ऐसे थे जिनमें हत्या जैसे गम्भीर अपराध का आरोप एक से अधिक बार लगा था साथ ही 15 आरोपी ऐसे थे जिन पर एक बार हत्या का आरोप था जबकि 19 लोग ऐसे भी थे जिन पर हत्या जैसे



बेबी रानी मौर्या
पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा

उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्या ने वाराणसी में महिलाओं को नसीहत दी कि अँधेरा होने के बाद थाने में न जाएं, बहुत जरुरी होने पर अगले दिन जाएँ और पिता, पति या भाई के साथ ही थाने जाएं।

गम्भीर आरोप एक भी बार नहीं लगा था बल्कि बहुत ही मामूली धाराओं में इन पर मुकदमें दर्ज थे। इसके अलावा इन आरोपियों पर न तो सशस्त्र विद्रोह का आरोप था न ही ये राजद्रोह या आतंकवाद फैलाने के आरोपी थे। मतलफ साफ है कि ये बहुत गम्भीर आरोपी नहीं थे।

फर्जी एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ

फर्जी एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ का विचार ही अपने आप में एक आपराधिक सोच है जिसमें अपराध को अपराध से समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस सोच को एक ऐसे राज्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता जहां विधि का शासन हो और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा चलता हो। पुलिस जो कि राज्य का एक अंग है उसका कर्तव्य है कि आरोपी को न्यायालय में पेश करे। यदि पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है तो यह उसकी अपनी ड्यूटी में विफलता है। निस्संदेह समाज में फैले अपराधों की रोकथाम तथा लोक व्यवस्था को सुचारू रखना पुलिस का कर्तव्य है। अपराधों की व्यापकता तथा आधुनिकता एवं नित्य बदलता स्वरूप, गम्भीर अपराधियों जैसे चरमपंथियों, आतंकवादियों, स्मगलरों आदि पर कार्यवाही एक कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन फिर भी अपराध पर रोक लगाने के नाम पर अपराधी को मार देने की नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे लोक कल्याणकारी तथा विधि के शासन को मानने वाले देश में फर्जी एनकाउंटर व कस्टोडियल डेथ की संस्कृति का पनपना 21वीं सदी के 21 वें साल में जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

फर्जी एनकाउंटर अधिकतर राजनीतिक कारणों से या पुलिसिया धमक को बनाये रखने के लिए होते हैं जबकि कस्टोडियल डेथ का सबसे जिम्मेदार कारण आर्थिक भ्रस्टाचार है। पुलिस किसी को भी इसलिए नहीं पीटती है कि वह उसे पीटकर मार डालना चाहती है जिसे वह मारना चाहेगी उसका फर्जी एनकाउंटर भी कर सकती है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को या तो इसलिए पीटती है कि अंग्रेजों के समय से ही यह गलत धारणा है कि वह किसी को जितना पीटेगी वह उतना ही अधिक पैसा देगा या उस व्यक्ति के किसी विरोधी से वह पहले ही इतना पैसा ले चुकी होती है कि उसकी कीमत चुकाने के लिए जो प्रताड़ना देती है उससे कई बार व्यक्ति की मौत हो जाती है।

बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर में 97 तथा कस्टोडियल डेथ में 25 लोगों की मौत हुई। कस्टोडियल डेथ के मामलों में बरेली जिले के ऑवला थाने में एक ऐसी घटना भी सामने आई जिसमें एक महिला की भी मृत्यु हुई है। एक पी आई एल के जबाव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल जबाव में 50 ऐसे लोगों की सूची न्यायालय के समक्ष रखी गयी जो एनकाउंटर में मारे गए थे। इन 48 लोगों के अपराधों की गम्भीरता की बात यदि की जाए तो इसमें केवल 14 लोग ऐसे थे जिन हत्या का आरोप एक से अधिक बार था जबकि 15 लोग ऐसे थे जिन पर हत्या का आरोप केवल एक बार लगा था तथा शेष 19 लोग ऐसे थे जिन हत्या के अतिरिक्त बहुत ही कम गम्भीर अपराधों के मुकदमें थे। इनमें से एक भी राजद्रोही, सशस्त्र विद्रोही या आतंकवादी नहीं था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 प्रावधान करती है कि गिरफ्तारी के समय किसी को भी जरूरत से ज्यादा जकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को हथकड़ी लगाना आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसका साफ तात्पर्य है कि पुलिस को यदि यह लगता है कि आरोपी भागने का प्रयास कर सकता है तो वह अनुमति ले सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश



अखिलेश यादव
पूर्व मुख्यमंत्री
उत्तरप्रदेश

कस्टोडिएल डेथ सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सबसे अधिक नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी है। फर्जी एनकाउंटर में भी उत्तर प्रदेश एक नम्बर पर है।




Tweet
Dilip Mandal
@Profdilipmandal
यूपी सरकार ने पुलिस की गलती से हुई मौत में भी जातिवाद कर दिया। लाश की क़ीमत भी अलग अलग लगाई जा रही है। शर्म करो और डूब मरो @myogiadityanath #JusticeforArunValmiki
Translate Tweet



नरेन्द्र सिंह
समाजिक कार्यकर्ता
बरेली, उत्तरप्रदेश

पुलिस एनकाउंटर में सरकार की ठोको नीति का सबसे बड़ा शिकार मुस्लिम रहा। सबसे बड़ी आश्चर्य जनक बात रही कि पुलिस एनकाउंटर में हिन्दुओं में सबसे अधिक ब्राम्हण मारे गये। नान यादव नान जाटव के फार्मूले पर काम कर रही वर्तमान सरकार में मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कि पुलिस एनकाउंटर में सबसे अधिक मरने वालों में मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी संख्या अहीरों की है जबकि स्थिति इससे उलट थी।

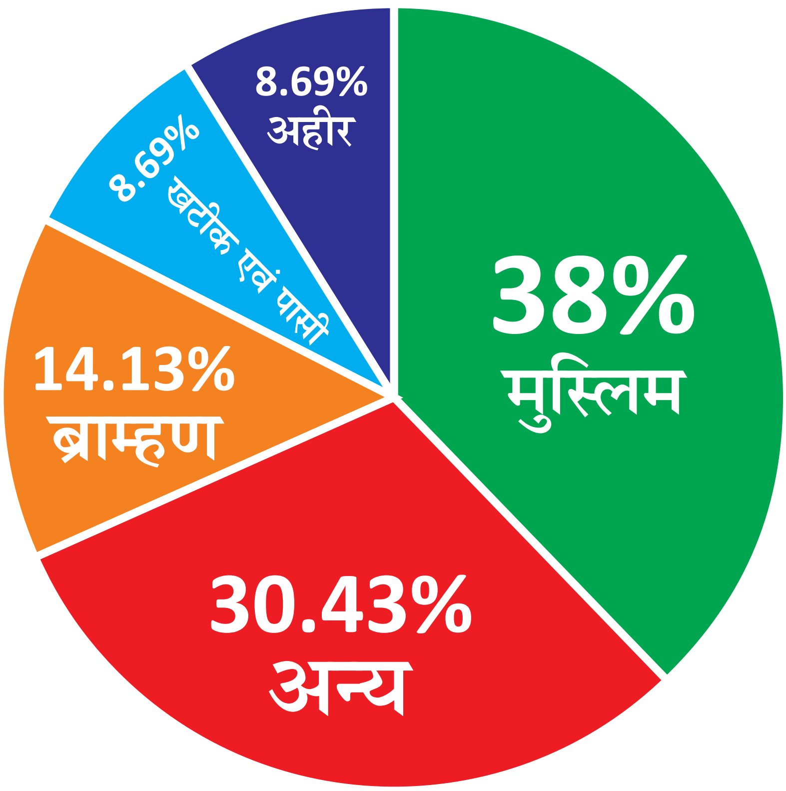


अप्रैल 17 से दिसंबर 2020 के मध्य पुलिस एनकाउंटर में हुई मौतें

इस अवधि के दौरान पुलिस एनकाउंटर में 93 मौतें हुई। मरने वालों में सबसे अधिक मुसलमान थे दूसरे नंबर पर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लोग ब्राहमण जाति से थे,इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या अहीरों की थी। पुलिस एनकाउंटर में कुल 08 अहीर मारे गए। वैसे जातिवार पुलिस एनकाउंटर में सबसे ज्यादा संख्या अहीरों की थी लेकिन ब्राहमणों का डेथ रेशियो अधिक रहा। 08 खटीक और पासी का एनकाउंटर में मौत हुई। पुलिस एनकाउंटर में जाट, गुर्जर, भर सहित कई जातियों के 29 लोगों की मौत हुई लेकिन जातिवार संख्या में सबसे अधिक ब्राहमण मरे गए। मुस्लिम -35, ब्राहमण- 13, अहीर- 08, खटीक एवं पासी - 08, अन्य - 28, कुल - 93

पुलिस द्वारा मरे गये लोगों को जाति देखकर मिलता है मुआवजा ?
सितम्बर 18 में लखनऊ के गोमतीनगर में एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस ने गोली मरकर कर हत्या कर दी। यूपी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। खुद सीएम योगी ने विवेक तिवारी के परिवार को 40 लाख का चेक दिया। सरकार की ओर से विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी को नगर निगम में सरकारी नौकरी दी गई।

में जितने भी लोगों की गिरफ्तारी के समय एनकाउंटर हुआ है किसी एक भी मामले में ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस ऐसा कोई आदेश प्राप्त कर गिरफ्तारी करने गयी हो। आखिर बार बार गिरफ्तारी के बाद रास्ते में आरोपी भागने का प्रयास करता है तो पुलिस ने किसी भी एक मामले में भी ऐसी अनुमति लेना क्यों ठीक नहीं समझा कि आरोपी को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि विकास दुबे जैसे व्यक्ति जिस पर गिरफ्तारी का विरोध करने में ही आठ पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप था उसकी गिरफ्तारी करने उत्तर प्रदेश पुलिस जब उज्जैन गयी तो उसे वहां तक पहुंचने में पर्याप्त समय मिला फिर भी उसे हथकड़ी लगाने का आदेश



नहीं लिया गया। और नतीजा यह हुआ कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उसने गाड़ी से हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया और वह मारा गया।

बात कस्टोडियल डेथ की करें तो पुलिस हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है यहां एक महिला की भी कस्टडी में मौत हुई है। हाल ही में



जौनपुर के बक्सा थाने में हुई पुजारी यादव की हिरासत में मौत की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जो कि कोर्ट की देख रेख में जांच कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में जौनपुर प्रशासन को फटकार लगाते हुए यहां तक कहा है कि हालांकि अन्वेषण राज्य का काम है लेकिन यदि इसके न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने में कोई शंका होगी तो न्यायालय भी इसकी जांच करा सकता है। इस मामले के अन्वेषण में लापरवाही को इसी से समझा जा सकता है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है लेकिन घटना के 9 महीने बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी वर्ष 2017 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य में हुए फर्जी एनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ व मानवाधिकार हनन जे 45 मामलों को सही पाया है व राज्य से सिफारिश की है कि ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाए ।

ये तो ऐसे मामले रहे जो मानवाधिकार आयोग या न्यायलय तक पहुचे, अब हम बात करें गाँव के लोगों की तो लोग कचहरी न जज कचहरी न जाना या की पिया जिन जाया कचहरिया वाले देश में सैकड़ों नहीं हजारों मामले सामने ही नहीं आते हैं। ▪

@ +91 9450512573



मनीष गुप्ता हत्याकांड

सितम्बर 2021 में गोरखपुर में युवा व्यवसायी मनीष गुप्ता की पुलिस वालों ने पीट पीटकर होटल में मार डाला मनीष अपने दो दोस्तों के साथ होटल में ठहरे थे सरकार ने परिवार को 40 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही।



अरुण वाल्मीकि मामला

आगरा के जगदीशपुर थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी के आरोप में अरुण वाल्मीकि नाम के सफाई कर्मचारी को पुलिस ने 19 अक्टूबर को अरेस्ट किया लेकिन उसी रात पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अरुण की मौत पुलिस की पिटाई से हुई। विवाद बढ़ा तो सरकार ने आरोपी पुलिसवालों पर एक्शन लिया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया। साथ ही मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।

सारी चर्चा इसी बात को लेकर है कि अगड़ी जाति के विवेक तिवारी और मनीष गुप्ता के परिवारों को योगी सरकार 40-40 लाख रुपये का मुआवजा देती है, लेकिन दलित समाज से आने वाले अरुण के परिवार वो 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, 'ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है?' इसको लेकर सामाजिक चिन्तक दिलीप सी मंडल ने अपनी प्रतिक्रिया दी।


← Tweet

Priyanka Gandhi Vadra
@priyankagandhi

किसी को पुलिस कस्टडी में पीट-पीटकर मार देना कहां का न्याय है?

आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन उप्र सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है

उच्चस्तरीय जांच व पुलिस वालों पर कार्रवाई हो व पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले

Translate Tweet

11:46 am · 20 Oct 21 · Twitter for iPhone



प्रशांत सिंह
एडवोकेट - हाई कोर्ट, लखनऊ

फर्जी एनकाउंटर करके किसी की हत्या करना, उसे विकलांग बना देना या पुलिस कस्टडी में पीट-पीट कर मार डालना ये सभी घटनाएं संविधान के अनुच्छेद 21 को सीधी सीधी चुनौती देती हैं और संविधान लागू होने के उद्देश्य को ही विफल करती हुई नजर आती हैं । इस तरह की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए ।

न्याय पूर्ण एवं न्याय संगत समाज के विकास एवं राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार ने बीसवीं सदी की अपनी पहली शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को जारी किया। जिसमें शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में देश का विजन क्या है, इसकी चर्चा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा एवं दिशा तय करेगी। इस नीति में कही गई बातें ना तो कानूनी बाध्यता है और ना ही तुरंत लागू होने वाली है। अपितु इनके क्रियान्वयन के लिए सरकारों को अलग से प्रयास करना पड़ता है।



नई शिक्षा नीति 2020 में नया क्या?

▪ डॉ. प्रमोद कुमार

इससे पहले भारत में दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968 और 1986) में आ चुकी थी। लेकिन उदारीकरण और सूचना क्रांति के बाद बदली हुई वैश्विक और रास्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता देश के लिए बड़े शिद्दत के साथ महसूश की जा रही थी। नई शिक्षा नीति के लिए इसके पहले जेएस वर्मा कमिटी, यशपाल कमेटी, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया लेकिन इनके द्वारा दिए गए मसौदे या तो सरकारों को पसंद नहीं आए या राजनीतिक कारणों से ठंडे बस्ते में डाल दिए गये।

जून 2017 में केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति हेतु 9 सदस्य कमेटी का गठन किया, जिन्होंने 23 माह बाद मई 2019 को अपना ड्राफ्ट केंद्र सरकार को सौंपा। इस ड्राफ्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति-2020 जारी किया।

वैसे इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई अहम बदलाव किए गए हैं लेकिन कुछ बदलाव जो पुरानी शिक्षा नीति से अलग हैं वह गौर करने लायक है।

स्कूली शिक्षा में बदलाव

अगर हम स्कूली शिक्षा में हुए बदलावो की बात करें तो अभी तक जो 10+2 की परंपरा थी वह अब खत्म हो जाएगी।इसकी जगह पर नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की बात की गई है।

5+3+3+4 में पाँच का मतलब है तीन साल का प्री-स्कूल और कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई, इसके बाद के तीन का मतलब है कक्षा 3, 4 और 5 तथा इसके बाद के तीन का मतलब है कक्षा 6, 7 और 8 और आखिर के चार का मतलब है कक्षा 9 10 11 और 12 की पढ़ाई।

जहां पहले बच्चे 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाते थे वही अब 3 वर्ष की उम्र में ही फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। इससे राइट टू एजुकेशन (RET) का विस्तार होगा साथ ही शुरुआती दौर में सीधे पहली कक्षा में प्रवेश देने की बजाय अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे मेथड को अपनाना भी उचित प्रस्ताव है। यूनिवर्सल बेसिक न्यूमैरेसी एंड लिटरेसीज जैसी अवधारणा को इसके साथ प्रस्तावित करना एक अच्छी पहल है। इस ढांचा को खड़ा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने तथा स्कूलों का एक परिसर (स्कूल कांप्लेक्स) बनाने का सुझाव दिया गया है।

भाषा के सवाल पर इस नीति ने बेहतरीन चालाकी की गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कि "जहां कहीं भी संभव हो" वहां पांचवी तक की पढ़ाई का माध्यम मातृ भाषा या स्थानीय भाषा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में यही दोहराते हैं कि जहां तक संभव हो पांचवी तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है।

इसका मतलब अगर मन करें तो मातृ भाषा में पढ़ाइए और अगर न मन करें तो अंग्रेजी में ही पढ़ाते रहिए। यानी सरकारी सलाह को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूलों में तो मातृ भाषा में पढ़ाई जारी रहेगी लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को ही महत्व







दिया जाएगा। इससे जहां हिंदी अंग्रेजी के बीच खाई बढ़ेगी वही सरकारी स्कूल में जहां आज भी लगभग 85 फीसदी छात्र-छात्रायें दलित और पिछड़े वर्ग के पढ़ते है उनकी मौलिक प्रतिभाएँ भाषा के अवरोध की वजह से दबी की दबी रह जाएगी।

वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश इस संबंध में कहते हैं कि वह प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षण के माध्यम को मातृभाषा में रखने के समर्थक हैं। लेकिन इसका पूर्णतया समर्थन तब दिया जाएगा जब सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों से लेकर दिल्ली और मुंबई के सबसे महंगे और एलीट स्कूलों में भी लागू किया जाए।

वह कहते हैं कि अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहेगा तो इसका हर कीमत पर विरोध होना चाहिए। यह देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और उत्पीडित तबके के साथ सरासर अन्याय होगा।

उच्च शिक्षा में बदलाव

इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा को लचीला बनाने की कोशिश की है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता मल्टीपल एंट्री-एक्जिट सिस्टम है।

अब ग्रेजुएशन (अंडर ग्रेजुएट) में छात्र चार साल का कोर्स पढ़ेगें, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है।

पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफ़िकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफ़िकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री, और चार साल बाद की डिग्री होगी शोध के साथ।

इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में तीन तरह के विकल्प होंगे। जिसके अंतर्गत जिन्होंने ग्रैजुएशन में तीन साल का डिग्री कोर्स किया है उनके लिए मास्टर कोर्स दो साल का होगा,जिन्होंने चार साल का कोर्स किया है उनके लिए मास्टर कोर्स एक साल का होगा। तीसरा विकल्प होगा, 5 साल का इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाए।

अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी चार साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा से संबंधित मल्टीडिसीप्लिनरी जैसी अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है। मल्टीडिसीप्लिनरी यानी एक से अधिक विषयों की पढ़ाई की संभावना। अभी तक यह होते आ रहा है कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो 4 साल केवल इंजीनियरिंग ही पढ़ता है। कोई मेडिकल पढ़ता है केवल मेडिकल ही पढ़ता है। केवल एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए कई सारे कॉलेज, टेक्निकल संस्थान खुले हुए हैं। यहां दूसरे विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन नई शिक्षा नीति से इस कमी को दूर करने की बात की गई है। यानी इंजीनियरिंग का विद्यार्थी टेक्निकल विषयों के साथ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय भी पढ़ें, ऐसे संस्थान बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

जानकारों का कहना है कि यह एक बढ़िया प्रस्ताव है। कोई विद्यार्थी केवल इंजीनियरिंग ही पढ़े लेकिन उसे समाज का नॉलेज न हो तो ऐसे ही लोग पढ़-लिखे होने के बावजूद भी कट्टरपंथी रवैया अपनाकर जीते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के तहत ग्रेडेड अटॉनोमी की भी बात कही गई है, जिसमें विश्वविद्यालयों के ऊपर से बोझ को कम किया जाएगा और कॉलेज को भी अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी। दरअसल इस ग्रेडेड अटॉनोमी के तहत नई शिक्षा नीति में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक प्रशासनिक इकाई बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियां आएंगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक संघों ने इस बोर्ड ऑफ गवर्नर सिस्टम का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार स्वायत्तता (अटॉनोमी) के नाम पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों पर अपना शिकंजा कसना चाहती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में अस्सिटेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं, "सुनने में स्वायत्तता शब्द बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसके पीछे सरकार की गलत मंशा है, जिसे अभी बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिये उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस के निर्धारण, अध्यापकों की वेतन और नियुक्तियों, पाठ्यक्रमों और अन्य अकादमिक कार्यक्रमों में अपना नियंत्रण चाहती है, जो कि स्वायत्तता के नाम पर छलावा और धोखा है।"

उच्च शिक्षा को अधिक केंद्रीकृत करने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड एजुकेशन (AICTE) और नेशनल कॉउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) जैसी संस्थाओं को किसी एक संस्था के अंतर्गत लाया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। हालांकि इसमें भी मेडिकल और लॉ शिक्षण संस्थानों को छूट दिया जाएगा। इसके अलावा शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की भी बात कही गई है।

इस नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देने के लिए शिक्षामित्र, एडहॉक, गेस्ट टीचर जैसी नियुक्तियों पर रोक की बात की गई है। स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में नियमित और स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की बात की गई है। लेकिन इस संबंध में डा. लक्ष्मण यादव कहते हैं कि शिक्षण संस्थानों में पहले से ही नियुक्ति प्रक्रिया रूकी हुई है, अब एडहॉक और गेस्ट टीचर की व्यवस्था खत्म कर सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, जिनको प्रति क्लास के आधार पर भुगतान मिलेगा।

सरकार ने नई शिक्षा नीति में जीडीपी का



विश्वविद्यालयो में महत्पूर्ण पदों पर आरएसएस,पार्टी विशेष और जाति विशेष से जुड़े साम्प्रदायिक पक्षपाती लोगो को बैठा कर कैसे आजाद ख्यालों की बात की जा सकती है? एक आजाद एजुकेशन सिस्टम एक आजाद समाज के बिना नहीं बन सकता है।

6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कहा है। दरसल 1986 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सरकारे यह बात कहती आ रही है लेकिन आज भी शिक्षा पर खर्च जीडीपी का 4 फीसदी के आस-पास बना हुआ है। और तो और मोदी सरकार के कार्यकाल में तो लगातार शिक्षा बजट को कम किया गया है। तो ऐसे में कैसे सरकार से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है?

आरएसएस की माँग मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलने की थी, जिसे अब एक बार फिर पहले की तरह शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

इस नई शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने जहां इसे 'ऐतिहासिक' बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई युग की शुरूआत बताया वही अनेक विद्वान इसकी तर्क संगत आलोचना भी करते है।

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पूर्व सदस्य और शिक्षा के क्षेत्र में ठीक-ठाक पकड़ रखने वाले प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने नई शिक्षा नीति के कई बिंदुओं को सराहा है। लेकिन महंगी होती शिक्षा के संदर्भ में प्रोफेसर योगेंद्र यादव का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के व्यवसायिकरण के बारे में 4,5 पैराग्राफ लिखे तो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे यह कहा जाए कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को खत्म करने के बारे में सरकार सुचिंतित तौर से सोच रही है।

इस दस्तावेज में क्रिटिकल थिंकिंग और आजाद ख्याली पर जोर दिया गया है। लेकिन हालिया माहौल को संदर्भ में जेएनयू,जामिया तथा देश के अन्य विश्वविद्यालयो में जो देखने को मिला है वह कथनी और करनी में फर्क ही दिखता है। विश्वविद्यालयों को डरा धमका कर और भगवाकरण को बढ़ावा देकर कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बात कैसे कर सकता है?

विश्वविद्यालयो में महत्पूर्ण पदों पर आरएसएस,पार्टी विशेष और जाति विशेष से जुड़े साम्प्रदायिक पक्षपाती लोगो को बैठा कर कैसे आजाद ख्यालों की बात की जा सकती है? एक आजाद एजुकेशन सिस्टम एक आजाद समाज के बिना नहीं बन सकता है।

देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर अनिल सदगोपाल इस शिक्षा नीति को आरएसएस से स्वीकृति लेने के बाद जारी किया गया ड्राफ्ट बताते हैं।वे कहते है इस शिक्षा नीति को मूलतः तीन बिंदुओं से देखने की ज़रूरत है। पहला- इससे शिक्षा में कॉरपोरेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा इससे उच्च शिक्षा के संस्थानों में अलग-अलग 'जातियाँ' बन जाएँगी, और तीसरा ख़तरा है अति-केंद्रीकरण का.

अनिल सदगोपाल इस पक्ष में अपने तर्क भी देते हैं कि नीति आयोग ने स्कूलों के लिए परिणाम-आधारित अनुदान देने की नीति लागू करने की बात पहले ही कह दी है।

ऐसे में जो स्कूल अच्छे होगें, वो और अच्छे होते चले जाएँगे और ख़राब स्कूल और अधिक ख़राब। ये हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट के मुक़ाबले कहाँ हैं। तो इससे फ़ायदा प्राइवेट वालों को ही होगा।अधिकतर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला वंचित समाज और हाशिए पर चला जायेगा।

शिक्षा से जुड़ें हुए आर.सी. मौर्या जी कहते है इस शिक्षा नीति में देश की 85 फीसदी वंचित वर्ग के लिए कुछ खास नहीं है। इससे शिक्षा का बाजारीकरण और बढ़ेगा और समाज में असमानता को बढ़ावा मिलेगा।

वे आरोप लगाते है कि इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन शब्द का जिक्र तक नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे संबोधन का बहुत कम उल्लेख है। जबकि भारत में सामाजिक आर्थिक हैसियत शिक्षा तक पहुंच तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के हर क्षेत्र में भागीदारी कम है। इनकी भागीदारी प्रोफेशनल कोर्स में कम है। ▪

@ +91 9452248223

आने वाले दिनों में कमर्शिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में धंधा करने वाले शिक्षण संस्थान सामाजिक न्याय की पॉलिसी अपनाएंगे ऐसा तो सोचना भी नामुमकिन लगता है। इस तरह से शिक्षा के बारे में जो एक प्रचलित कहावत है कि शिक्षा अगर समाज में असमानता कम करने का काम करती है तो चुपचाप तरीके से असमानता को जन्म भी देती रहती है। और शिक्षा द्वारा पैदा हो रही असमानता खत्म होते दिखे या कम हो जाए, ऐसा इस नई शिक्षा नीति से नहीं दिखता।



ऑनलाइन शिक्षा : आपदा में अवसर

▪ नरेन्द्र प्रताप

कोरोना की शुरुआत के बाद पिछले लगभग 17 महीनों से भारत में सभी स्कूल बन्द हैं बीच- बीच में कुछ समय के लिए जरूर बड़ी क्लासेज - के लिए स्कूल खोले गए। समय आ गया है कि हम गहराई से विचार करें कि क्या ये स्कूल बच्चों की सुरक्षा के नजरिये से बन्द किए गए या कोरोना की आड में एक अलग तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा हा कृपया इन पहलूओं पर ध्यान दें।

आईसीएमआ, एम्स, यूनिसेफ व यूनिस्को ने समय पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि वैज्ञानिक आधार पर 15 वर्ष से छोटे बच्चों को कोरोना की वजह से किसी भी तरह की गंभीर खतरे की आशंका नहीं है।

> विश्वभर में लगभग 190 से ज्यादा देशों में स्कूल सिर्फ 4 या 5 महीने बंद रहे। भारत वो अकेला देश है जहां स्कूल इतने लंबे समय तक बंद रहे। स्वीडन, फ्रांस व कुछ अन्य यूरोपीय देशों में तो अपने यहाँ एक भी दिन स्कूल बंद नहीं किए और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यहाँ पर कोरोना के मामले अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले कम केस सामने आए ।

बड़े स्कूलों को होने वाला आर्थिक लाभ पूरे निजी शिक्षा क्षेत्र को मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जा सकता है -

बड़े एलीट प्रीमियम स्कूल- जहाँ पर वार्षिक फीस कम से कम 1 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है। ऐसे अधिकतर स्कूल बड़े शहरों में है। इन स्कूलों में आमतौर पर धनाड्य वर्ग अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उत्सुक रहता है। ऐसे सभी स्कूलों में कोरोना काल में 90 प्रतिशत से ज़्यादा फीस समय से पहले आ गई। लेकिन स्थिति का फायदा उठाते हुए इन सभी ने लगभग एक चौथाई शिक्षकों से इस्तीफा ले लिया और बचे हुए स्टाफ को आमतौर पर 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया। नतीजा ये हुआ कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने से ऐसे सभी प्रीमियम स्कूलों का कुल लाभ तीन से चार गुना बढ़ गया। यह भी हम सब को अच्छे से मालूम है कि ऐसे सभी बड़े स्कूलों का ग्रुप किसी न किसी बड़े राजनेता की हिस्सेदारी है। इसीलिए कोरोना की आड़ में ये स्कूल ज्यादा से ज्यादा समय बंद रहे।

शैक्षिक अंतराल में वृद्धि- जहाँ देश के लगभग 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के साधन उपलब्ध है। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10 करोड़ बच्चे व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 10 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 4 करोड़ बच्चों के पास ही ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभावशाली साधन उपलब्ध हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 28 करोड़ स्कूली बच्चों में से सिर्फ 7 करोड़ स्कूली बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और 21 करोड़ बच्चे पूरी तरह से शिक्षा से पिछले 18 महीनों से वंचित हैं। इसका सीधा असर आने वाले समय में यह होगा कि यह 21 करोड़ बच्चे इस लर्निंग गेप की वजह से आने वाले समय में शिक्षा से पिछड़ते चले जायेंगे। सरकारी स्कूलों के कॉरपोटाईजेशन की रणनीति एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना की आड़ में सरकारी स्कूलों को बंद रखकर भविष्य में उनकी स्थिति को खराब कर भविष्य में कुछ खास कॉरपोरेट घरानों को सौंपने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

टेस्ट बुक्स में बदलाव- एक खास विचारधारा को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है

बॉयजू बनाम बैजनाथ

बॉयजू शिक्षा का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जिसका व्यवसाय करोड़ो में है, जबकि बैजनाथ एक आम शिक्षक। बॉयजू के सामने बैजनाथ कैसे टिकेंगे। बॉयजू जब भी जब भी चाहेंगें किसी फाइव स्टार होटल में फिक्की के अंतर्गत मीटिंग करेंगें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उस मीटिंग का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा की नीतियां तय करेंगें। जबकि बैजनाथ सारी गणित और भूगोल के बावजूद डीआईओएस के सामने अपने हक के लिए खड़े भी नही हो सकते हैं। एक तरफ बॉयजू ऑनलाइन शिक्षा का मास्टर है दूसरी तरफ बैजनाथ का छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन आवेदन भी स्वीकृत नही होता है। बॉयजू के सामने बैजनाथ कहाँ टिकेंगें।

इस पेज का शेष लेख पेज नं.-11 में है

भारतीय इतिहास में शिक्षा



बौध कालीन शिक्षा व्यवस्था- भारत में शिक्षा का व्यवस्थित प्रयास बौद्धों के द्वारा हो सका प्राचीन भारत में आधुनिक प्रकार की पुस्तकालय और देश तक्षशिला, सिरपुर, नालंदा में बड़ें बड़ें विश्वविद्यालयों का संचालन बौद्धों की कुशल शिक्षा व्यवस्था की ओर इशारा करता है जिसमें भारत ही नहीं विदेशों से बड़ी संख्या में शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे।

▪ अर्जुन इलाहाबादी

भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षित होना या नौकरी करना ही नहीं अपितु इंसान के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है इसमें कोई शक नहीं है कि समय समय पर शिक्षा नीतियों में बदलाव होते रहे है। प्राचीन भारतीय शिक्षा और शिक्षा पद्धति, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा में जातीय प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जिस समय काल में जिन जातियों का प्रभुत्व था शिक्षा व्यवस्था उसी के अनुसार रही। इन तीनो समयावधियों में शिक्षा जन सामान्य से नहीं जुड़ पाई कमोबेश स्थिति आज भी वही है, देश का एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से दूर है।

प्राचीन भारत में शिक्षा



प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य वेदों से हुआ वैदिक काल में एक उचित समय पर बालकों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रूप में भेजा जाता था जो विभिन्न संस्कारों के उपरांत प्रारंभ होती थी प्राचीन भारतीय शिक्षकों के प्रमुख उद्देश्यों में क्रमशः नैतिक चरित्र का निर्माण करना पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना व्यक्ति का विकास करना सामाजिक कुशलता की उन्नति करना संस्कृति का संरक्षण करना तथा चरित्र निर्माण करना एवं जीवों को प्यार करना था।

स्टूडेंट्स को अपना शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास करने के अवसर प्रदान किए गए शिक्षा की प्रवृत्ति यद्यपि धर्म प्रधान एवं आध्यात्मिक थी परंतु भौतिक समृद्धि योजना नहीं की जा सकती थी फिर भी प्राचीन शिक्षा में बहुतायत कमियां भी देखने को मिलती हैं जैसे धर्म को अधिक महत्व देना स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा सूत्रों की शिक्षा की उपेक्षा जनसामान्य की शिक्षा की उपेक्षा लोक भाषाओं की उपेक्षा विचार स्वतंत्रता का अभाव सामाजिक जीवन की उपेक्षा शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि एवं नवीन धर्मों की अवहेलना आदि।

मध्य काल में शिक्षा

12 वीं शताब्दी से लेकर 18 वीं शताब्दी तक भारत पर मुस्लिमों का अधिकार रहा मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे प्राचीन काल की शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा से हटकर मध्यकालीन शिक्षा थी।

गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश तथा लोदी वंश के बाद मुगलों ने भारत पर राज किया मुस्लिम शासक ज्यादातर पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को शरण दी भारतीय संस्कृति में मुस्लिमों ने जो परिवर्तन किए उनमें शिक्षा भी अछूती नहीं रही मुस्लिम संस्थाओं ने अपनी नई शिक्षा पद्धति के विकास पर ध्यान दिया



और मदरसों की स्थापना की इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया यहां यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि मुस्लिम शासकों ने भारतीय स्कूलों गुरुकुलों को बहुत हानि पहुंचाई इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसी भी हद तक गए भारतीय विश्वविद्यालय और भारतीय विद्वानों को निर्दयता से नष्ट किया मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं या उद्देश्य इस्लामी धर्म का प्रचार-प्रसार करना इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना मुस्लिमों के ज्ञान का प्रसार करना मुस्लिम शासक को सुधार करना एवं सांसारिक ईश्वर की प्राप्ति करना परंतु इसके बाद भी मुस्लिम शिक्षा में बहुत कमियां देखी थी जैसे इस्लाम के कट्टर विचार लोक भाषाओं की उपेक्षा स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, शिक्षा के भौतिक पक्ष पर बल, हिंदुओं की शिक्षाओं की उपेक्षा, कठोर शारीरिक दंड, शिक्षा में व्यापकता का अभाव आदि जैसी कमियां थी।



आधुनिक कालीन शिक्षा नीति

ब्रिटिश भारतीय द्वारा स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1601 में व्यापार करने के लिए भारत आई और फिर भारतीय इतिहास में शिक्षा की एक क्रांतिकारी दौर की शुरुआत हुई कंपनी भारतीयों को अपनी बात कहने के लिए एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना चाहती थी कि भारतीय कंपनी के बीच भाषा की समस्या उत्पन्न ना हो लेकिन कालांतर में यही अंग्रेजी भाषा भारत के लिए कल्याणकारी साबित हुई। अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करने के लिए कंपनी के माध्यम से ईसाई मिशनरियों की सहायता ली इसके लिए ईसाई मिशनरियों ने नये पैटर्न के स्कूलों की स्थापना की जो भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत थी इसी क्रम में 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आए।

आधुनिक शिक्षा में निकाली का योगदान टीवी मैकाले ने अब तक चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को नकार दिया। उसने अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा की प्रबल संस्था की उसने संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा साहित्य को निकृष्ट वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्न कहा। उसने फ्रेंच व अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य को उत्कृष्ट कहा उसने कहा कि एक अच्छे यूरोपी पुस्तकालय की अलमारी का सहित भारत भारत के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। अतः सर्वविदित है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को ही माना जाता है। सन् 1854 में कंपनी ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया उड्स डिस्पैच कहा जाता है इस घोषणापत्र से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शिक्षा पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया। ▪

@ +91 8707440780

ऑनलाइन शिक्षा : आपदा में अवसर - पेज नं.-9 का शेष...

> **ऑनलाइन डेटको कम्पनियां व डिजिटल कम्पनियां को प्रोत्साहन** - स्कूलों को बंद रखने का सबसे बड़ा राज रिलायन्स व जियो जैसी डाटा काम्पनियां व बॉयजू, वेदांतु आदि डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म वाली कम्पनियों को बहुत कम समय में कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इसलिए इन कम्पनियों को ये बड़ा आर्थिक लाभ ऐसे ही जारी रहे इसके लिए स्कूलों का बंद रहना बहुत जरूरी है।

कि स्कूली स्तर पर ही उनको इस तरह की किताबे उपलब्ध कराई जाएं जो अभी तक के पढ़ाए जा रहे इतिहास में कुछ बड़े बदलाव को करने के बाद पढ़ाई जाएं इसीलिए इतने लंबे समय तक स्कूल बंद रखकर इन पब्लिसर्स को आर्थिक तौर से कमजोर कर कुछ अपने खास चहेते पब्लिसर्स के माध्यम से इन नई किताबों के प्रकाशन की तैयारी चल रही है।

सफेद पोश जॉब्स के लिए बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा - पिछले कुछ वर्षों में भारत की विकास दर 2015 में प्लस 8 प्रतिशत से लुढ़कती हुई 2015 में माइनस 11 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। इसका सीधा प्रभाव बड़े पैमाने की बेरोजगारी में हुआ जो अब संभवतः पिछले 50 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। नतीजा ये हुआ कि शिक्षित बेरोजगार करोडों की तादात में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे रहें। जब कि सरकार लाखों की तादात में नौकरी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत सरकार की ये कोशिश है कि एजुकेटेड वर्क फोर्स को कम किया जाए और उसकी जगह लेबर की संख्या को बढ़ाया जाए। जिससे बड़े औद्योगिक घरानों को कम दरों पर श्रमिक उपलब्ध हों। स्कूल बंद रखने से युनिसेफ के ताजा आंकडों के अनुसार करोड़ों से ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूल बंद रहने की वजह से स्कूल को छोड़कर अब गरीबी की वजह से मजदूर बन चुके हैं। ▪

आज चरवाहा विश्वविद्यालय होता तो क्या होता?

▪ **नरेन्द्र प्रताप**



आज से 30 साल पहले चरवाहा विश्वविद्यालय का नाम जब आया था तो भैंस पर चढ़कर चलते हुए अफसरों के कार्टून खूब छपे थे। लालू प्रसाद की भले ही खूब खिल्ली उड़ाई गई थी लेकिन यदि आज चरवाहा विश्वविद्यालय होता तो क्या होता? कभी चरवाहा विद्यालय को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव की पूरी दुनिया में चर्चा भी हुई और हँसी भी उड़ाई गई। लेकिन उत्तर भारत में पशुओ और किसानों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसका समाधान शायद इसी तरह के विश्व विद्यालयो को खोजना था। सरकार का पशु प्रेम, और किसानों के लिए पशु समस्या की खाई बढ़ा रही है। आवारा और अनुपयोगी पशु किसानों और पशु के बीच संघर्ष/लड़ाई में बदलता जा रहा है।



चरवाहा कार्य हजारों वर्षो से चला आ रहा है। चरवाहों के बारे में तो यहां तक कहा जाता है भारत में तो चरवाहों ने ही शहरों और गावों की बसावट की प्रक्रिया को अंजाम दिया। प्रो0 कांचा आइलैय्या का मानना है कि मैदानों, पहाड़ों और जंगली जानवरों की सबसे अच्छी जानकारी यादवो के पास ही है। गावों का विस्तार गढ़रियों की इन्ही खोजों पर पर निर्भर करता था। बाद में बसावट जहां नदियों के मिलन स्थल थे वहां किये गये। गांव के बसावट को के पीछे जिन चरवाहों का इतना बड़ा योगदान रहा, उनपर भारत में अभी तक कोई शोध नहीं हुआ। लोगों ने जेएनयू, जामिया और वर्धा जैसी युनिवर्सिटियों से पत्रकारिता में बड़ी-बड़ी डिग्री ले डाली लेकिन इनके ऊपर भारत में कोई ढंग की एचडी तक नहीं हुई।

एक मानव धरती पर आया, एक व्यक्ति हुआ जिसके चाहे विचारों से ही जैसे छत्तीसगढ़ में गोबर से गोवर्धन बन गया उसी तरह से चरवाहों का विश्वविद्यालय बना होता तो आज 30 सालों में वहां के बच्चे जवान हो गए होते। वहां से निकलने वाले बच्चे पीएचडी कर नए नए विचार दे रहे होते तो। रोजगार कैसे हमें पशुओं में तलाशने हैं? कैसी गांव की परेशानी है? कैसे सिरपुर से लेकर हड़प्पा और नालंदा जैसे शहर बसे और उजड़ने से कैसे नहीं बच पाए? यह बसावट की प्रक्रिया थी उसको लेकर चरवाहों की बड़ी भूमिका रही है। इसपर रिसर्च नहीं हुई। भारत में हजारों साल से लोग अनपढ़ थे लेकिन तब भी बसावट प्रक्रिया जारी थी।

भले ही आज चरवाहे किसी वैज्ञानिक गणना में शामिल न होते हो लेकिन चरवाहों का परंपरागत ज्ञान आधुनिक जीवन का

पहले दुनिया में सिर्फ चरवाहे हुआ करते थे। उनकी जाति ही चरवाहा कहलाती थी। धीरे-धीरे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग जाति और धर्म के चरवाहे होने लगे। हिन्दू और मुसलमान जैसे धर्मो में बंट गये। दुनियां में आज भी जो चरवाहे है उनकी कोई जाति थोड़े न है, वे चरवाहों की ही जाति है। ये चरवाहे आज जाति की जकड़न में फंस गये है अहीर, गढ़ेरिया, पासी, गद्दी गुज्जर बक्करवाल। उनके अविष्कार बंद हो गये है। जरूरत है इस चरवाहा कल्चर को जाति की जकड़न से मुक्त कराने की। इनकी मुक्ति अंबेडकर के जात-पन्त का विनाश के माध्यम से हो सकेगी या संविधान में इसके लिए खिड़कियां और दरवाजे हैं।



आधार बना हुआ है। चुम्बक की खोज से लेकर कर जावन/जमावन का अविष्कार चरवाहा वैज्ञानिकता का ही परिणाम है, चरवाहे के चुम्बक की शक्ति को पहचान कर ही डायनेमो और विधुत मोटर का निर्माण संभव हो सका। आज हम कम्प्यूटर युग में पहुंच सके है। चुम्बक के गुणों को पहचान कर नौ परिवहन को सुगम बनाया जा सका। आज भले ही चरवाहे किताबी ज्ञान से महरुम है लेकिन उनके परंपरागत ज्ञान-विज्ञानं पर शोध किया जाय तो काफी हद तक दुनिया का भला हो सकता है।

यदि चरवाहों पर ठीक दिशा में रिसर्च की जाती तो हम पशुपालन के बहाने हमें कई अनुत्तरित प्रशो के उत्तर मिल गए होते। हमने चरवाही के माध्यम से भैंस की सवारी की, घोड़े की सवारी की, यहाँ तक कि हाथी जैसे विशालकाय जीव की भी सवारी की लेकिन शेर की सवारी कभी नहीं की। शेर की सवारी आस्था का विषय है इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। भैस की सवारी को यमराज की सवारी क्यों बना डाला? अगर लोग पढ़ रहे होते। चरवाहा विश्वविद्यालय बना होता तो इस बात पर की यमराज भैसे पर आये उनकी खिल्ली नहीं उड़ाई गयी जब भैस पर चढ़कर एक अफसर जा रहा है तो उसकी इतनी खिल्ली उड़ाई गयी। संचार विशेषज्ञ डॉ. नरेश कुमार साहू का मानना है कि यदि चरवाहा विश्वविद्यालय बना होता तो निश्चित तौर पर आज यमराज पर भी पीएचडी हो गई होती, यमराज भैसे पर क्यों बैठते है, 90 के दशक में चरवाहों पर कार्टून क्यों बने? बसावट कैसे हुयी? और सबसे महत्वपूर्ण चरवाहों की जाति या बसावट का जाति से क्या लेना देना है?

चरवाहे कुछ ही जातियों से क्यों है ? 90 के दशक में चरवाहा जाति के लोग कैसे मुख्यमंत्री पद की सवारी करने लगे ? सुअर चराते चराते राम विलास पासवान, गाय भैस चराने वाले लालू यादव, मूस की पूँछ पकड़कर जतिन राम मांझी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गये तो चरवाहा यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने वाला लड़का एस पी नहीं बन सकता कि डी एस पी नहीं बन सकता कि डाक्टर नहीं बन सकता कि प्रोफेसर नहीं बन सकता ? शायद लोग इस बात के लिए डरते थे इसीलिए चरवाहा विश्वविद्यालय की जड़ जमते ही जमुआ लग गया।

इतना उसका मजाक बनाया गया कि उसको जमाने ही नहीं दिया गया, बीज ही नहीं पनपने दिया गया। आज चरवाहा विश्वविद्यालय होता तो अकल बड़ी या भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराय, गई भैंस पानी में जैसे मुहावरे प्रयोग में नहीं होते।

जब तक चरवाहा संस्कृति हमारे जीवन से नहीं पनपेगी तबतक हमारा गोबर धन नहीं बन पायेगा। गाय की चर्बी और मांस पर समुचित शोध होना चाहिए, हमारे यहाँ हजारों साल से चमड़े का कारोबार करनेवाले इन्ही चरवाहों पर आश्रित थे जिन्होंने इससे ढोल और मृदंग बनाना और बजाना सीख लिया लेकिन बड़े बड़े कलाकार ढोल के नहीं दे पाए, पदम् श्री नहीं ले पाए। इनपर भी शोध होना चाहिए की चरवाहों के जीवन से इनका क्या लेना देना है?

एक समय था कि चरवाहा कल्चर या चरवाहा संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े परिवर्तन हुए है चरवाहों ने ही किये है चुम्बक की खोज किसी चरवाहे ने की थी, जो आधुनिक जीवन का आधार है चुम्बक न होता तो बिजली न होती।

ईसा मसीह, मुहम्मद साहब और कृष्ण भी चरवाहे थे, आज भी बहुत से ऐसे लोग है जो भैस चराते चराते इंजिनीयर डॉक्टर और अधिकारी बन गये। आज चरवाहा विद्यालय/विश्वविद्यालय खोले होते जहाँ गाय भैस भेड़ बकरी चराते चराते बच्चे आनंद पूर्वक पढ़ना लिखना सीखा करते, भारत की अधिकतर जनसँख्या शिक्षित हो चुकी होती। अब न सिर्फ चरवाहों बल्कि तमाम दलित बहुजनो को अपने चरवाहा विद्यालय खोलने चाहिए। ▪

__बसावन इंडिया हिंदी मासिक पत्रिका का__ संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुँचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाति है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानाकर्षण करेंगें। साथ ही आप अपके लेख और विचार basavanindia@gmail.com पर स्वागत करतें हैं। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करे। यदि जगह के आभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमे इंतजार रहेगा।

लोकतंत्र पर धब्बा : किसान सामुहिक हत्याकांड

▪ **मैत्रेयी सिंह**

3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जो भी हुआ पूरे देश को झंझोर कर रख दिया अब तक लोग किस्से और कहानियों में सुना और पढ़ा करते थे कि राजतन्त्र में विरोधियों को हाथियों के पैरों तले लोगो को कुचलवा दिया जाता था या तानाशाहों द्वारा शौकिया तौर पर ऐसे खेलों का आयोजन किया जाता था जिसमें लोगों की जान चली जाया करती थी, अब न तो ऐसे राजतंत्र बचे हैं और न ही ऐसे शौक। यह शौकिया तौर पर था या सनक कि लखीमपुर में 4 किसानों को हूटर बजाती लग्जरी गाड़ियों से रौंद दिया जाता है वो दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र में। क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं था?

मामला क्या था?

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर जिले के बनबीरपुर में आयोजित था। तिकोनिया-बनबीरपुर मार्ग पर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर तेजी से आती दो एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) कुचलते हुए निकल जाती हैं जो आगे जा कर असंतुलित होकर पलट जाती हैं, चार लोगों की मौत घटना स्थल पर ही जाती है कई किसान गंभीर रूप से घायल हो हैं। साथी किसानों की मौत से किसान आक्रोशित हो उठते है इस दौरान एसयूवी सवार लोगों द्वारा पिस्टल से फायरिंग कर शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़का कर हिंसक बना दिया जाता है। गाड़ी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा फायरिंग करते हुए भाग निकले। किसानों को रौंदने वाली गाड़ियों में सबसे आगे थार थी, उसके बाद काले रंग की फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी थी और इसके पीछे स्कॉर्पियो थी। घटना से नाराज़ लोगों ने थार और फ़ॉर्च्यूनर में आग लगा दी थी। लेकिन स्कॉर्पियो में बैठे लोग बच निकले थे।

कौन है अजय मिश्र टेनी?

लखीमपुर खीरी की खीरी लोकसभा सीट से दो बार के सांसद अजय मिश्रा उर्फ टेनी को मोदी के कैबिनेट विस्तार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया। 2022 के यूपी विधानसभा इलेक्शन में ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए बाहुबली सांसद अजय मिश्रा की लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच समेत कई जिलों में ब्राह्मण जाति का सिरमौर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अजय मिश्र मोदी खेमें के माने जाते हैं।

इस घटना से पूर्व में अजय मिश्र किसानों को दो मिनट में सुधार देने की धमकी दे चुके हैं। इससे पूर्व उनका एक विडिओ वायरल हुआ था जिसमें वे किसानों को धमकी भरे अंदाज में उसकने का प्रयास कर रहे हैं।



सरकार का रवैया

खीरी में किसानों की हत्या को मैनेज करने की कोशिश पुलिस द्वारा लगातार होती रही पुलिस दबाव में रही जिसकी वजह से वह कार्यवाही करने से बचती रही लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डांट और विपक्ष के दबाव के बाद पुलिस ने हत्या के मुख्य अभियुक्त आशीष और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ़्तार किए गए लोगों में सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन सिंह बिष्ट और सत्य प्रकाश त्रिपाठी हैं। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सत्य प्रकाश त्रिपाठी से लाइसेंसी रिवॉल्वर और तीन गोलियां मिली हैं। सुमित जायसवाल बीजेपी का नेता है। वह किसानों को रौंदने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी में मौजूद था और घटना के बाद बचकर भाग निकला था।

घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें वह साफ दिखाई दिया था। इसके बाद मौक़े पर भगदड़ मच गई थी। गुस्साए किसानों ने गाड़ियों में मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया था। किसानों के द्वारा एफ़आईआर दर्ज कराने के बाद सुमित जायसवाल ने भी इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने आशीष मिश्रा के काफिले पर हमला कर दिया था। लेकिन किसानों को रौंदे जाने के वीडियो सामने आने के बाद जायसवाल की बात झूठ निकली थी।

लखीमपुर की घटना को लेकर

भाजपा का रवैया

हत्या के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के अहम ओहदे अभी तक बना रहना और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न किया जाना भारतीय जनता पार्टी के ढीठ रवैये को दर्शाता है।

भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व के इस रवैये से यह बात सामने आती है कि वह हर हाल में सही है और उसके लोगों द्वारा किया हर कृत्व किसी भी स्थिति में सही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आयोग से कहा गया है कि वह दो महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे।

योगी सरकार ने फ़ैसला लिया था कि रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। यह भी फ़ैसला लिया गया था कि घटना में मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने यह सहायता राशि परिजनों को दे दी है। घायलों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी एलान किया गया था।



जब जब लोगों की जान गयी तब कांग्रेस में जान आई ...

इसे आपदा कहा जाए या अवसर कि जब-जब प्रदेश में लोगों की जान गयी तब-तब कांग्रेस में जान आई। मतलब की अब कांग्रेस मुद्दे विहीन हो चुकी है, कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व तभी सक्रिय हुआ है। जब-जब प्रदेश में कोई चर्चित हत्या या सामूहिक हत्या कांड हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दे जो लोगों को रोज प्रभावित कर रहे है उनपर कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व कभी भी कोई आन्दोलन नहीं पैदा कर सका। सिर्फ और सिर्फ हत्याकांड जैसे मुद्दों पर पर जनाक्रोश को भुनाने की कोशिश रही हैं चाहे वह हाथरस कांड रहा हो या फिर लखीमपुर खीरी में किसानों का सामूहिक नरसंहार में कांग्रेस ने खुलकर राजनीति की। इन मुद्दों पर कांग्रेस की नूराकुश्ती कुछ इस तरह से दिखती है जैसे असली विपक्षी दल कांग्रेस हो। सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में शायद यही कारण है की सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं का सड़क पर अधिक खून गिरता है कई मुद्दों पर तो सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जानवरों जैसा सुलूक किया है। सडकों पर ही खूब पीटा हैं यहाँ तक कि निवर्तमान सांसद धर्मेन्द्र यादव पर इलाहाबाद में आन्दोलन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई उनका सर फूट गया, बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता घायल हुए।





विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर शुरुआत में तो किसी भी राजनीतिक दल को लखीमपुर खीरी घटना में मरे गए लोगों के परिजनों से नहीं मिलने देना चाह रही थी लेकिन राजनीतिक दलों के बढ़ाते दबाव और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की हो रही किरकिरी से सरकार को झुकना पड़ा। कई दिनों की मशक्कत के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लखीमपुर जाने की अनुमति मिल गई। सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव, कांग्रेस से प्रियंका और राहुल गाँधी, प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव, आप नेता संजय सिंह सहित अन्य प्रमुख नेता पीड़ित परिवारों के परिजनों से मिले। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला।

क्या निष्पक्ष जाँच संभव है?

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह "नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फ़ॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट आपके व्यवहार से मिलेगा।" से स्पष्ट है की भाजपा में अंदरूनी रूप से सब कुछ ठीक ठक नहीं चल रहा है। 2022 के चुनावों के मद्दे नजर पार्टी जरूर यह कोशिश करेगी की आशीष मिश्रा बच जायं यदि अगर पुलिस की जांच में यह बात साबित हो गई कि किसानों को कुचलने वाली गाड़ियों में आशीष मिश्रा मौजूद था, तो यूपी के चुनाव में यह भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है। अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट में बना रहना पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है कि भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व अभी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दोषी नहीं मान रहा है ऐसे में पार्टी के स्तर पर जरूर ऐसे प्रयास किये जायेंगे की आशीष मिश्रा बेदाग निकल जाएं और घटना का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ दिया जाए। ■

@ +91 9453790069

आजमगढ़ : थानेदारी में हिस्सेदारी

■ **बसावन इंडिया डेस्क**

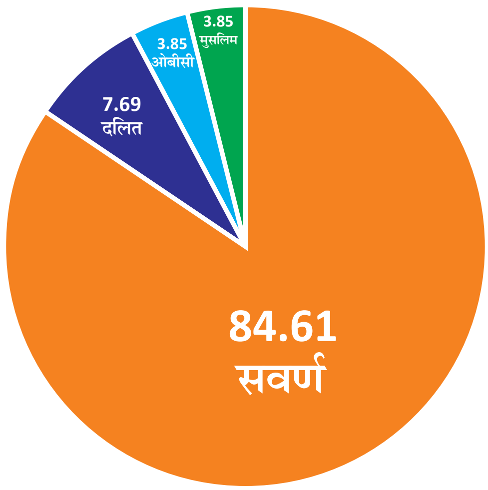
इलाहाबाद से लखनऊ गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान दो पुलिस कर्मी आपस में बातों ही बातों में बताया कि सोनभद्र जिले के 22 थानों में से 18 थानों पर सवर्ण जातियों के थानेदार तैनात है, शेष 2 अहीर और 2 थानों के बारे में स्पष्ट जानकारी नही दे सके। जिज्ञासावश बसावन इंडिया ने कुछ जिलों की पड़ताल की और अपने नेटवर्क से सही जानकारी जुटाने की कोशिश की। जाति आधारित जनगणना भले ही मुश्किल कार्य है लेकिन सरकार में भागीदारी/ अधिकारियों/ कर्मचारियों की गणना का कार्य आसान है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बहुत ही जोर शोर के साथ मंत्रियों की जाति का जोर शोर के साथ प्रचार किया गया। यदि मंत्रिमंडल विस्तार में में जाति आधारित गणना की जा सकती है है तो कर्मचारियों की गणना क्यों नही? थानेदारों की गणना को लेकर बसावन इंडिया ने आजमगढ़ जिले के थानों में तैनात सभी थानेदारों की गणना अपने सूत्रों से की है। बसावन इंडिया टीम ने आजमगढ़ जिले के 26 थानों के थानेदारों की जातिवार जनगणना का प्रकाशन इस बार कर रही है। जिसमे सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जातियों की भागीदारी का प्रकाशन जातिवार किया जा रहा है। बसावन इंडिया सरकार के सबका साथ सबका विकास की पड़ताल अपने स्तर से करने का प्रयास कर रही है।

क्र.	थाने का नाम	थानेदार का नाम	जाति
1	अहिरौला	संजय सिंह	क्षत्रिय
2	अतरौलिया	राजेश सिंह	क्षत्रिय
3	बरदह	रूद्र भान पांडेय	ब्राह्मण
4	बिलरियागंज	धर्मेंद्र कुमार सिंह	क्षत्रिय
5	दीदारगंज	हिमेंद्र सिंह	क्षत्रिय
6	देव गांव	शशि मौली पांडेय	ब्राह्मण
7	गम्भीरपुर	धर्मेन्द्र कुमार	क्षत्रिय
8	जहानागंज	गजानंद चौबे	ब्राहमण
9	जीयनपुर	दिनेश यादव	अहीर
10	कन्धरापुर	कमल नयन दूबे	ब्राहमण
11	कप्तानगंज	बिन्द कुमार	अनुसूचित जाति
12	शहर कोतवाली	धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव	कायस्थ
13	महाराजगंज	नदीम फरीदी	मुसलमान
14	मेहनगर	विमल प्रकाश राय	भूमिहार
15	मेहनाजपुर	सुरेन्द्र सिंह	क्षत्रिय
16	महिला थाना	मधु कणिका	सवर्ण
17	मुबारकपुर	योगेंद्र बहादुर सिंह	क्षत्रिय
18	निजामाबाद	यादवेंद्र पांडे	ब्राहमण
19	पवई	ब्रहाम्दीन पांडेय	ब्राहमण
20	फूलपुर	धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय	ब्राहमण
21	रानी की सराय	दिलीप कुमार सिंह	क्षत्रिय
22	रौनापार	अखिलेश चंद्र पांडे	ब्राहमण
23	सरायमीर	स्वतंत्र कुमार सिंह	क्षत्रिय
24	सिधारी	जीतेन्द्र कुमार सिंह	क्षत्रिय
25	तहबरपुर	अनुराग कुमार	अनुसूचित जाति
26	तरवां	सुरेंद्र प्रताप सिंह	क्षत्रिय

आजमगढ़ जिले के 26 थानाध्यक्षों में 12 क्षत्रिय, 7 ब्राहमण, 1 भूमिहार, 1 कायस्थ 1 मुसलमान, 1 अहीर और 2 अनुसूचित जातियों से हैं। महिला थाना प्रभारी मधु कणिका हैं जिनकी जाति का पता तो नही चल पाया लेकिन बताया गया कि वो भी सवर्ण कैटेगरी से बताई गयी। इस प्रकार 26 में से 22 सवर्ण जातियां हैं। आजमगढ़ जिले के 85 प्रतिशत थानेदार सवर्ण जातियों से हैं। शेष जातियों में दो अनुसूचित जातियां, एक मुसलमान, और एक अहीर जाति से है। प्रदेश की प्रमुख ओबीसी में जातियों में कुर्मी, अहीर, कोइरी, भर, लोहार, कोंहार, कहार, नाई, गड़ेरिया का आजमगढ़ के थानेदारों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। आजमगढ़ की थानेदारी में कुर्मी, कोइरी, भर, लोहार, कोंहार, कहार जाति के किसी भी थानेदार को कोई जगह नही मिली है ओबीसी जातियों के प्रतिनिधित्व के रूप में जीयनपुर थाने में एक थानेदार के रूप में एक अहीर की उपस्थिति है। आजमगढ़ जिले में अनुसूचित जाति वर्ग से दो थानेदार तैनात हैं, जिनकी जाति का पता तो नही चल पाया। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लंबी लिस्ट है उनमे से किसी दो जाति से दो थानेदारों को तैनाती दी गयी है शेष जातियों का जिले में प्रतिनिधित्व शून्य है। जबकि सरकार ने सबका साथ सबका विकास का दावा किया था। ■



सामाजिक चेतना परिषद् के संयोजक मनोज कुमार का कहना है कि हमें मंत्री तो चाहिए था, पर थानेदार भी चाहिए। 70 प्रतिशत न्याय / अन्याय थाने स्तर पर ही निपटा दिए जाते हैं। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता की याद दिलाती है कि खेत ठाकुर का, मुठिया ठाकुर की। अब तो आधा थाना भी ठाकुर का हो गया आजमगढ़ में।



जातीय जनगणना रिपोर्ट

महादेवा काशीराम, महाराजगंज उत्तर प्रदेश

आज जब की जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में उठ रही है, विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया के मनगढ़त आकड़ों द्वारा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत ब्राहमण और ओबीसी की आबादी 42 प्रतिशत है, जबकि 40 साल पहले तैयार की गई मंडल रिपोर्ट में भी ओबीसी की जिसमें की 3743 जातियां शामिल थी, को देश की कुल जनसँख्या का 52 प्रतिशत बताया गया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किये जाने के बाद कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, इसके आलावा ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में ही शामिल किया गया। ओबीसी में जातियों की संख्या और प्रतिशत दोनों बढ़ा। ऐसे में बसावन इंडिया रेंडमली किसी जिले की किसी गांव का चयन कर जातीय जनगणना की तीसरी रिपोर्ट को छपता है। कहा जाता है की बानगी के लिए एक चावल ही पर्याप्त होता है।

बसावन इंडिया के प्रवेशांक में आजमगढ़ जिले के भरमा-डढ़िया ग्राम सभा की जातीय जनगणना का प्रकाशन किया था। बसावन इंडिया ने अपने दूसरे अंक में संत रविदास नगर के भक्तापुर ग्राम सभा की रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। तीसरे अंक के लिए अंबेडकरनगर जिले की सेहरी लहिया ग्रामसभा की जातीय जनगणना रिपोर्ट का सफलता पूर्वक प्रकाशन किया।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा। जातीय जनगणना की इस कड़ी में बसावन इंडिया की संपादकीय टीम ने महादेवा काशीराम, महाराजगंज उत्तर प्रदेश का चयन किया हैं जिसे उसी गांव के निवासी आदित्य ने तैयार की है। आदित्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर हैं और पत्रकारिता का कोर्स किये हुए हैं।

महादेवा काशीराम ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 726 है। जिसमें अहीर, चमार, कुर्मी, कांहर, नाई, लोहार, तेली, ब्राह्मण, कोंहर, धोबी, पासी और लोनिया सहित कुल 12 जातियां हैं।

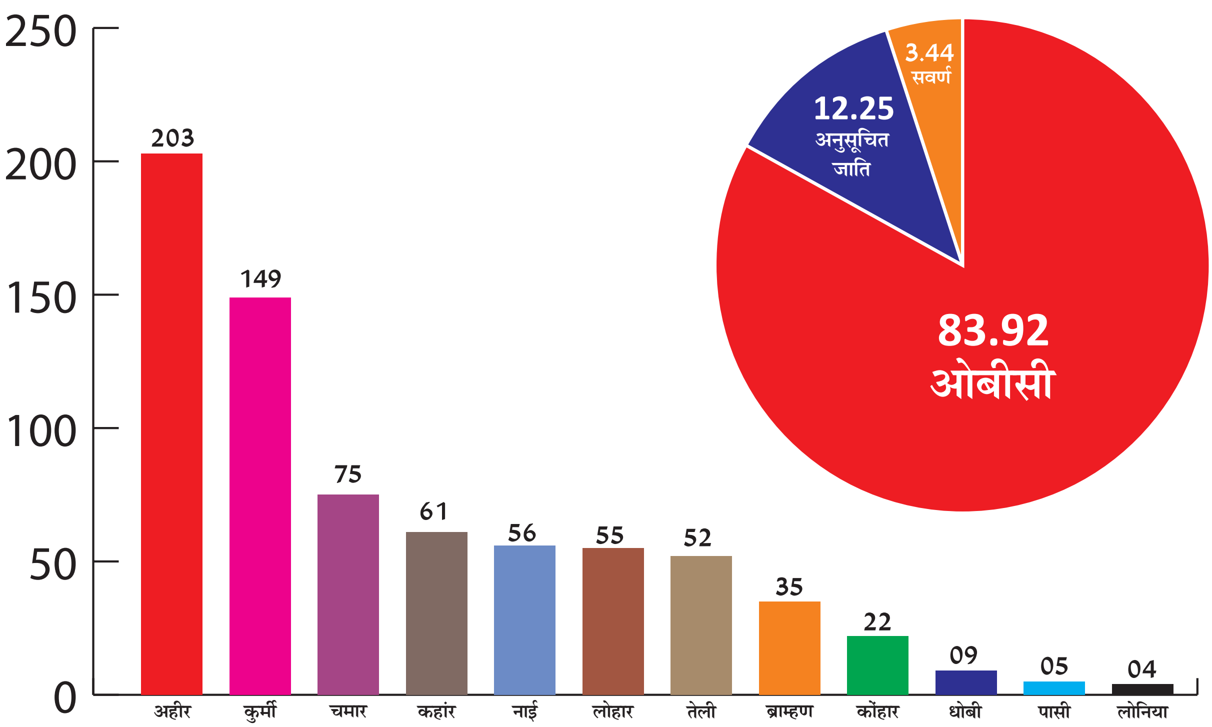
महादेवा काशीराम ग्रामसभा पिछड़ा बाहुल्य है। पिछड़ी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 602 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 83 फीसदी है। पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या अहीर मतदाताओं की है जिनकी संख्या 203 है। दूसरी पिछड़ी जातियों में कुर्मी मतदाता 149, कहांर मतदाता 61, नाई 56,लोहार 55, तेली 52,कोंहार 22 और लोनिया 04 हैं।

अनुसूचित जातियों में महादेवा काशीराम ग्रामसभा चमार,धोबी और पासी मतदाता है। अनुसूचित जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 89 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 12.26 फीसदी है। ग्रामसभा में चमारों की संख्या सबसे अधिक 75 है। धोबी मतदाताओं की संख्या 09 और पासी मतदाताओं की संख्या 05 है।

सवर्ण मतदाताओं में महादेवा काशीराम ग्रामसभा में सिर्फ ब्राह्मण मतदाता हैं जिनकी संख्या 35 है। कुल मतदाताओं ब्राह्मणों की भागीदारी 3.44 फीसदी है। ▪



आदित्य कुमार
सिटीजन जर्नलिस्ट



ग्राम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 के अनुसार महादेवा काशीराम, महाराजगंज उत्तर प्रदेश के जातिवार गणना

उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक दशा

जनता का नजरिया बनाम पार्टियों का नजरिया

■ कँवल भारती



उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक दशा पर सोचने के दो तरीके हैं, एक, जनता के नजरिए से और दो, पार्टियों के नजरिए से. अगर हम जनता के नजरिए से देखें, तो हाल-फिलहाल की स्थिति यह है कि उसकी कोई राजनीतिक सोच अभी तक नहीं बन सकी है। वह हिंदू-मुस्लिम में बंटी हुई है। जो मुस्लिम हैं, वे सपा के पक्ष में हैं, और जो हिंदू हैं, उनमें भी दलित-सवर्ण विभाजन हैं। जो दलित हैं, उनमें चमार और जाटवों को छोड़कर, जिसका बड़ा धड़ा बसपा के साथ जा सकता है, शेष मायावती की ब्राह्मण-राजनीति से हताश हैं। इनके सिवा अधिकांश दलित भाजपा के ही साथ हैं। सवर्ण वर्ग में भी एक वर्ग ओबीसी का है, जिसमें यादवों का बहुमत सपा के साथ है, और शेष सारे ओबीसी और सारे सवर्ण भाजपा के समर्थक हैं। इस लिहाज से उत्तरप्रदेश में भाजपा का पलड़ा अभी भी भारी है। जनता की यह स्थिति एक दशक पहले तक नहीं थी. यह स्थिति 2014 में केन्द्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद पैदा हुई।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद आरएसएस और उसके सगठन भी ताकत में आए और साथ ही उनका हिंदू एजेंडा भी सत्ता-संपन्न हुआ. सबसे पहले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की भावना पैदा करने की रणनीतिक राजनीति शुरू हुई। यह राजनीति कामयाब हो गई, क्योंकि साम्प्रदायिक दंगों ने इसका माहौल पहले से ही बना रखा था. उसके बाद भाजपा ने आरक्षण की नई रणनीति बनाकर दलितों में महादलित और पिछड़ों में महापिछड़ा नाम के दो नए वर्ग बनाए। इस प्रकार भाजपा और आरएसएस ने जागरूक और राजनीतिक परिपक्वता वाले चमार और जाटवों को दलितों से तथा यादवों को पिछड़े वर्ग से अलग करने के लिए यह दुष्प्रचार किया कि आरक्षण का सारा लाभ चमार-जाटवों और यादवों को मिल रहा है। इस दुष्प्रचार ने जादू का काम किया, और इसलिए किया, क्योंकि महादलित तथा महापिछड़े शिक्षित और राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। इसलिए वे आसानी से दुष्प्रचार में फंस गए। भाजपा ने इसी अशिक्षित और अपरिपक्व महादलित-महापिछड़ा वर्ग को हिंदुत्व से जोड़कर अपना अंधा समर्थक बना लिया. अब यह विशाल वर्ग कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम-विरोधी बना हुआ है, जो भाजपा की एक बड़ी ताकत है। भाजपा और आरएसएस के नीतिकार जानते हैं कि वे केवल द्विजों के बल पर सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी संख्या भाजपा को बहुमत दिलाने लायक नहीं है। इसलिए उन्हें दलित और पिछड़ी जातियों का वोट चाहिए ही. पर वोट के बदले भाजपा और आरएसएस दलित-पिछड़ी जातियों का विकास नहीं चाहते।

विकास उन्हें द्विजों का ही करना है। दलित-पिछड़ी जातियों को उन्हें वर्णव्यवस्था के तहत द्विजों का सेवक बनाना ही अभीष्ट है। इसमें वे सफल हो गए। अब दलित-पिछड़ी जातियों के इस विशाल वर्ग को केवल हिंदुत्व की रक्षा करना है और मुसलमानों से लड़ना है। न उन्हें शिक्षा की जरूरत है और न विकास की. वे विकास का अर्थ जानते भी नहीं. इसका कारण यह है कि यह मेहनतकश दिहाड़ी मजदूरों और अपने हाथ से कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोगों का वर्ग है। ये अपने बच्चों को हुनर सिखाते हैं, शिक्षा नहीं दिलाते. हालाँकि उनके आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं हैं कि वे अपने बच्चों को ऊँची तालीम दिला सकें। आरएसएस और भाजपा के लिए यह एक नायाब नुस्खा भी है। इसलिए उनकी भी कोशिश ऐसी ही नीतियां बनाने की रहती है कि यह वर्ग ऊँची शिक्षा हासिल न कर सके.

अब पार्टियों के नजरिए से देखते हैं कि आने वाले चुनावों में उत्तरप्रदेश की दलीय राजनीति किस करवट बैठेगी? फिलहाल, चुनाव मैदान में सभी विपक्षी दलों ने ताल ठोकी हुई है। पर जितनी बुरी दशा उनकी आज दिखाई दे रही है, उतनी पहले कभी नहीं थी. यह बुरी दशा किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि सपा (समाजवादी पार्टी), बसपा (बहुजन समाज पार्टी) और कांग्रेस तीनों की यही स्थिति है। इनमें कुछ छोटे दल भी शामिल हैं, जो जिस पार्टी की हवा होती है, उसी में शामिल हो जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आप (आम आदमी पार्टी) भी बिजली-पानी फ्री देने के वादे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये सभी दल भाजपा को हराना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि अगर सभी का लक्ष्य भाजपा को हराना है, तो ये मिलकर एक होकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या ये अलग-अलग लड़कर भाजपा को हरा सकेंगे? अगर इनमें से हरेक यह समझ रहा है कि वह अकेले ही भाजपा को हराने में सक्षम है, तो जाहिर है कि वे बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं।

एक होकर न लड़ने का कारण क्या है? इसका कारण है कि इनके पास वे मुद्दे ही नहीं हैं, जिनका वास्ता जनता की समस्याओं से है। जाहिर है कि इस तरह की स्थिति तभी पैदा होती है, जब पार्टियां जनता के हितों से

पूरी तरह कट जाती हैं। ऐसी पार्टियां अपने चापलूस और दलाल किस्म के नेताओं की आँखों से देखती हैं, उन्हीं के कानों से सुनती हैं और उन्हीं की जुबान से बोलती हैं। सतीश मिश्रा बसपा सुप्रीमो मायावती को समझाते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने से पार्टी सत्ता में आ सकती है। इधर सतीश मिश्रा ने समझाया और उधर बसपा ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण-सम्मेलन शुरू कर दिए। फिर सपा के सलाहकार नेता भी क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कान भर दिए कि आप भी ब्राह्मणों को लुभाइए, उनके परशुराम भगवान का जयकारा लगाइए और उनकी विशाल मूर्ति लगवाने का वादा कीजिए. अब इन तीन प्रतिशत ब्राह्मणों को अपने-अपने पाले में लाने की राजनीति में बसपा और सपा एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दौड़ किए जा रहे हैं। इस दौड़ में न सपा को विशाल पिछड़ी जातियों की समस्याएं दिखाई दे रही हैं और न बसपा को दलित जातियों का दर्द। उनकी रैलियों में पूरे प्रदेश से पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक आते हैं, तो उनकी भीड़ देखकर वे समझते हैं कि बस! अब उनकी ही सरकार बनने जा रही है।

इनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाजपा ने इनकी जमीन को ही कमजोर कर दिया है। जिन जातियों और समुदाओं को ये अपना वोट बैंक समझते थे, उसका अधिकांश हिस्सा अब भाजपा के खाते में चला गया है। जो शेष बचा है, उसको भी बचाने की चिंता छोड़कर वे अपना फोकस ब्राह्मणों पर कर रहे हैं, जो अपने वर्चस्व वाली भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले. एक और बात सपा-बसपा सुप्रीमो की समझ में यह भी नहीं आ रही है कि प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मणों के एजेंडे पर चलने वाली भाजपा को छोड़कर दलित-ओबीसी आधार वाली और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली पार्टियों को क्यों पसंद करेगा? दलित-पिछड़े भी उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सपा-बसपा सत्ता में आने के बाद



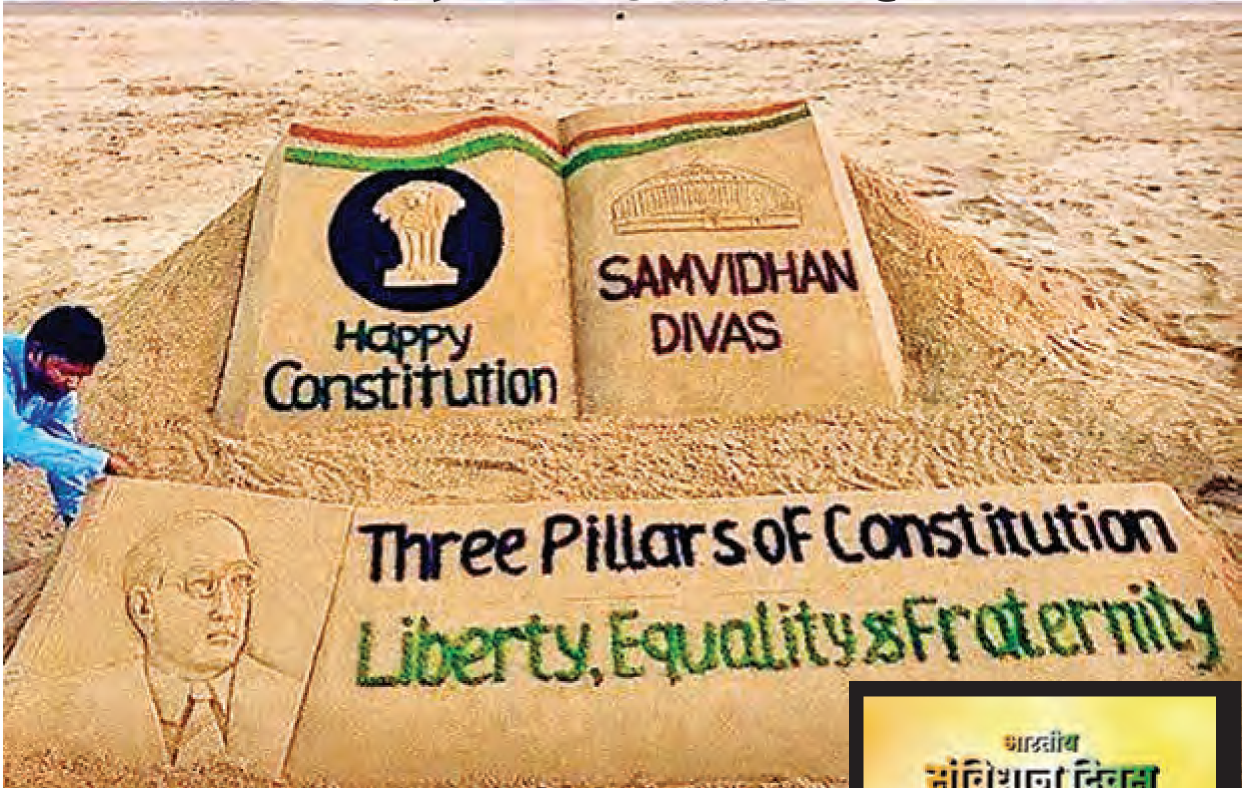
दलित-ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे, जो ब्राह्मण चाहते हैं? क्या सपा-बसपा दलितों पर ब्राह्मणों का अत्याचार निर्बाध रूप से होने देंगे, जो ब्राह्मण चाहते हैं? यदि ये पार्टियां ऐसा करेंगी, तो उनके ताबूत में आखरी कील भी उनका यह ब्राह्मण-प्रेम ही ठोकेगा।

कांग्रेस को लेते हैं। इसके नेता राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी निश्चित रूप से प्रदेश में अपना जनाधार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे किसानों की समस्याओं पर सपा और बसपा के मुकाबले ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं, और जहाँ-जहाँ किसानों के धरना-प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। लेकिन फिर भी वे अपने खोए हुए जनाधार को पुनः कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी का भी राजनीतिक फोकस अपर कास्ट को ही लुभाने पर दिखाई देता है, वे मंदिर, जनेऊ और गंगा की बातें कर रहे हैं, और अभी बनारस की रैली में उन्होंने राष्ट्रवाद को भी उभारा। इससे लगता है कि राजनीति में 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' की कहावत कांग्रेस पर ज्यादा फिट बैठती है।

उत्तरप्रदेश में कांग्रेस लगभग तीन दशकों से सत्ता से बाहर है। 1989 में नारायणदत्त तिवारी की सरकार के बाद कांग्रेस का जो पतन हुआ, उससे वह आज तक नहीं उभर सकी है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वह उन कारणों पर मंथन करे और उनको दूर करे, जिनसे वह कमजोर हुई। वे कारण हैं, उसके सिंहासन के वे तीन पाय–दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक (खासकर मुसलमान), जो 1990 के बाद मंडल-कमंडल आन्दोलन के दौरान उससे टूट गए थे. इस दिशा में कांग्रेस का कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। उसका फोकस न दलितों पर है, न पिछड़ों पर और न मुसलमानों पर. कांग्रेस का अपना एजेंडा क्या है, ईद पर वह राजनीति नहीं कर रही है। राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी द्वारा तीनों कृषि कानूनों का विरोध और चंद पूंजीपति घरानों को भारत के संसाधन बेचे जाने के मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ उनकी आवाज से यह पता नहीं चलता है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पर क्या निर्णय लेगी? वह तीनों कानून रद्द करेगी और बेचे गए संसाधनों को वापस लेगी या नहीं? इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस ने जनता की सहानुभूति हासिल की है, पर यह सहानुभूति वोट में कितना बदलेगी, यह कहना मुश्किल है। बिखरा हुआ और दिशाहीन विपक्ष क्या उस भाजपा का मुकाबला कर पायेगा, जो संगठित भी है, अपने लक्ष्य के साथ भी है। भाजपा का मतलब मोदी या योगी नहीं है, बल्कि हिंदुत्ववाद है, और विपक्ष उसके विरुद्ध अगर धर्मनिरपेक्षतावाद की संगठित राजनीति नहीं करता है, तो उनके लिए सत्ता अभी दूर की कौड़ी है। ▪

@ +91 9412871013

लोकतंत्र की आत्मा : संविधान



■ **बसावन इंडिया डेस्क**

केंद्र सरकार 26 नवम्बर 2015 से संविधान दिवस मना रही है। संविधान दिवस मानाने का सिलसिला संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125 वी जयंती से शुरू हुआ है, वैसे संविधान दिवस तो देश में बहुजन तबके के लोग पहले से मानते आ रहे है। दलित समुदाय के लोग घरों में रोशनी करते हैं, संविधान के मुख्य वास्तुकार अंबेडकर के योगदान पर सेमिनार करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं और बच्चों की भाषण प्रतियोगिता कराते हैं। भारत का बहुजन तबका संविधान दिवस को निरपेक्ष भाव से मनाता रहा है, यह जाति धर्म और अन्य संकीर्णताओं से ऊपर उठकर है। संविधान लागू होंने के पश्चात उसे उसके अधिकार मिले भले ही वह वास्तविक धरातल पर धीरे धीरे उतर रहा है। भारतीय संविधान को 73 वर्ष हो गये। एक तरह से कहा जाय तो हमारे संविधान का 73वां जन्मदिन है। 73 साल में तीन पीढ़ियां बीत जाती है। कुछ तो खास है हमारे संविधान में, आज भी युवा बना हुआ है नमन उस शिल्पकार को जिसने इसे तराशा...नमन डॉ. आंबेडकर, जिन्हें इस बात का पूरा पूरा भान/अंदेशा था कि संविधान को कैसे कैसे झंझावातों का सामना करना पड़ेगा। किस तरह से उसे पंगु बनाने के लिए चालें चली जायेंगी।

इमारत के हर पत्थर की तरह हर एक अनुच्छेद को चुन चुन के रखा। उसकी खूबसूरती पर कोई असर न पड़े। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। संविधान में दिए गये सामजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार जो देश वासियों की बहुत बड़ी जरुरत है। लेकिन आज देश को स्वतन्त्र हुए 75 साल हो रहे हैं, अभी तो लोग ठीक से स्वतंत्र हो भी नहीं पाए थे की फिर से उन्हें परतन्त्र बनाने के षड्यंत्र शुरू हो गये हैं। आज सौन्दर्यीकरण के नाम पर उसे विकृत करने की कोशिशें की जा रही है। उसके एक एक अंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी संविधान प्रदत्त आरक्षण के साथ खिलवाड़ तो कभी महिला सुरक्षा के नाम पर महिला अधिकारों के हनन की कोशिश। लव जेहाद के नाम पर युवाओ से उनकी आजादी छीनने की कोशिश।

सामाजिक और आर्थिक हैसियत के मुताबिक संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो लोगों के दिमाग में इस बात को बैठा दिया गया कि आरक्षण रोजगार प्राप्ति



बाबा साहब का अनुमान था कि आर्थिक और सामाजिक असमानता बनी रही तो भारत के वंचित विद्रोह कर देंगे। ये बात उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कही भी थी. उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को भारत अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश करेगा। राजनीतिक जीवन में समानता होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी बनी हुई है। उन्होंने संविधान सभा को चेतावनी दी थी कि अगर इन असमानताओं को समाप्त न किया गया, तो वंचित लोगों का गुस्सा संविधान द्वारा निर्मित लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर देगा।

का साधन है। 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दिया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण तो पहले से था, आज मेडिकल डिग्री(एम बी बी एस) की डिग्री के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। आई आई टी की फीस 24 लाख किये जाने की बात की जा रही है। 10, 20 या फिर 50 हजार प्रतिमाह कमाने वाला पिछड़ा या दलित का होनहार छात्र कैसे इसके बारे में सोच सकता है फिर उसके पास तो पुस्तैनी दौलत भी तो नहीं है।

अब बात सिर्फ सामाजिक और आर्थिक स्तर से ऊपर निकल कर मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पहुंच गयी है। अब तो वह एमबीबीएस और आई आईटी के बारे में सोच भी नहीं सकता और सोच भी लेगा तो परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं रहेंगी। समस्या यहाँ तक तो जो है वो है ही इससे आगे भी यदि किसी प्रकार वो एडमिशन ले भी ले तो उसके सहपाठी उसे जीने नहीं देंगे। रोहित बेमुला को भूल चुके हों तो मुम्बई की पायल तड़वी को ले लीजिय देश के सबसे ऊँची मेडिकल संस्था में महिला डॉ. को आत्महत्या के लिये बाध्य होना पड़ता है। विभाग के वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर द्वारा महिला डॉक्टर को लगातार परेशान किया जा रहा था। फैकल्टी मेंबर डॉक्टर की जाति और महिला होने को लेकर उसे ताने मारता था, वह महिला डॉक्टर की क्षमताओं पर सवाल उठाता था और कहता था कि तुम्हें कुछ आता-जाता नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा।ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। उन्हें आर्थिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों स्तर पर लड़ना पड़ता है।

संविधान ने व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की छूट दी है, जो उसका निजी मामला है लेकिन आज भारत के कुछ राज्यों में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वो दूसरे धर्म को नहीं मान सकता है, कोई मजिस्ट्रेट किसी को धर्मांतरण की अनुमति क्यों देगा? सच तो यह है कि अपनी विशेषताओं के कारण संविधान कुछ लोगों के आँखों की किरकिरी बन गया है। उस दौर में वापस जाने की कोशिशें जारी है जहाँ मार-मार के भंगी बनाया जाता है जाहिर है कि कोई अपनी इच्छा से तो भंगी बना नहीं होगा। किसी ने खुद के लिए बेड़ियाँ और बंधन नहीं चुनी होगी। बंधन में तो जानवर रखे जाते हैं देश में एक ऐसा भी दौर था जब इंसान भी बंधन में रखे जाते थे। चालाकी और कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए जाति व्यवस्था को जन्म दिया।

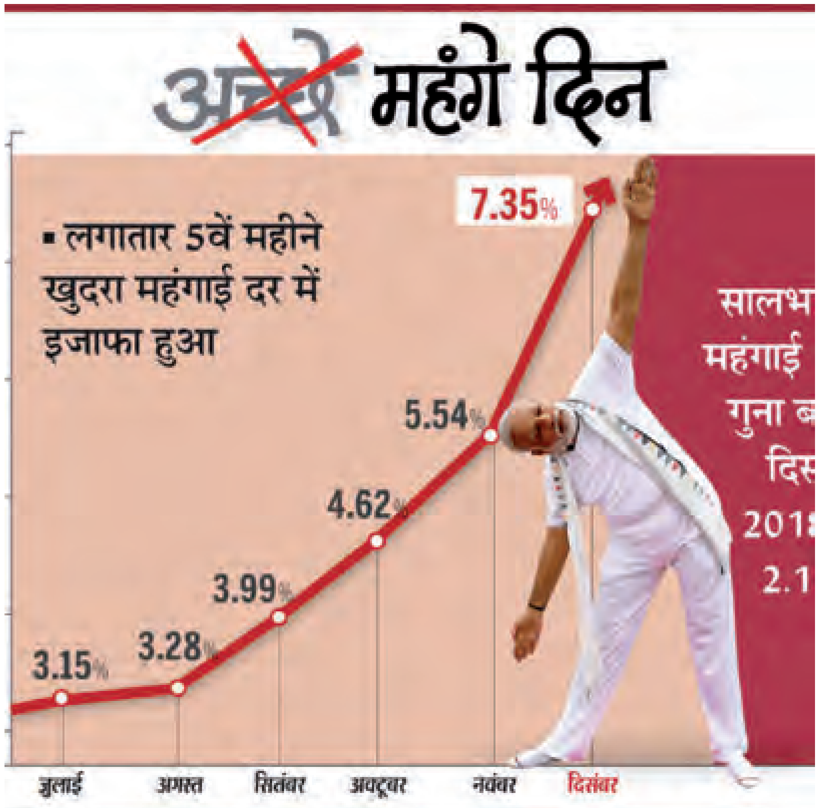
एस.टी./ एस.सी. तो संविधान के महत्व को समझ गया है कि उसकी मुक्ति के रास्ते संविधान में हैं लेकिन ओबीसी अभी तक नहीं समझ पाया कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। अभी तक वह अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर परिभाषित करने में विफल है, अब भी मनुवादियों के साथ संविधान को समाप्त करने के लिए सबसे आगे खड़ा है। मनुवादी व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। ▪

बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार .....

महंगाई को महसूस करना हो तो कही भी बाजार में जाकर खड़े हो जाईये। पेट्रोल डीजल पंप पर ही नहीं सब्जी के दुकान तक में आपको देखने सुनने को मिल जाएगा कि सब्जी तेल में तो आग लगी है। ऐसा नहीं है कि महंगाई से गरीब लोगों का ही बुरा हाल है। अच्छे-अच्छे पैसे वाले भी महंगाई से त्रस्त हैं। सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है। अरे भाई पेट्रोल डीजल आपके हाथ में नहीं है लेकिन खाने वाले तेल और दूसरे सामानों में तो है। आखिर ऐसा क्या देश में ईमरजेंसी आ गई कि खाने वाला सरसों का तेल 90 रु. से बढ़कर 250 रु. पर बाजार में मिल रहा है। यही नहीं कोई भी बाजार में उत्पाद है सबके दामों में बढ़ोत्तरी है। बाबा रामदेव हो या अडानी अंबानी, कोई देशहित में नहीं सोच रहे कि लोगों का जीना वैसे ही कोरोना ने दूभर कर रखा हैं उपर से महंगाई ने आम आदमी की पूरी कमर ही तोड़ कर रख दी है।

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भारत की बढ़ती महंगाई दर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 30 साल के उच्च स्तर पर है, जिससे देश के लिए "बहुत खतरनाक" स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि इससे हाइपरइन्फ्लेशन का कोई जोखिम नहीं दिखता। बसु ने कहा "आम तौर पर थोक मूल्य मुद्रास्फीति खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति में फैल जाती है, इसलिए यह भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। साल 2009 से 2012 के दौरान भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले बसु ने पॉलिसीमेकर्स जर्नलः फ्रॉम न्यू डेल्ही टू वाशिंगटन डी. सी नामक एक नई पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत जोखिम भरे मोड़ पर है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को आपस में जोड़ने की जरूरत है। भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी बसु की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में मुद्रास्फीति के बारे में पहले की तुलना में अधिक चिंतित हैं।

उधर मोदी की सरकार महंगाई पर कुछ सोच रही है ऐसा नहीं लगता। अब जब कुछ



राज्यों में विधान सभा के उपचुनावों में पार्टी को सिकस्त मिली तो कुछ महिनों में ही अगले साल राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसे देखते हुए मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम में 5 रु. और डीजल के दाम में 10 रु. की कमी की है। अब इवेंट तो बनना ही था। सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक सब जुट गए इसे बड़ी इवेंट बनाने में। राज्य सरकारों पर खास कर कांग्रेस और अन्य राज्यों के उपर बजरंगियों ने झुंड बनाकर राज्य सरकारों पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने को लेकर दबाव बनाना शुरु कर दिया।जैसे हमेशा होता है कि जैसे ही राज्यों में चुनाव की आहट होती है वैसे ही सरकारी अमला और अधिकारी वोट के लिए जनता को भरमाने में जुट जाता है।

मई 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुपात में तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए थी, मोदी जी लगातार अपनी चुनावी रैली में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर यूपीए की कड़ी आलोचना कर रहे थे, बीजेपी के बड़े-बड़े नेता संसद के सामने पेट्रोल डीजल ओर गैस सिलेंडर की महंगी कीमतों के खिलाफ नाच नाच कर प्रदर्शन करते थे

याद है न "बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार"

मई 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई कुछ दिनों में फिर कच्चे तेल का बाज़ार पलटने लगा

जनवरी 2016 तक कच्चे तेल के दाम 34 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क गए। मोदी सरकार ने कच्चे तेल की गिरावट की रैली का खूब फ़ायदा उठाया। इस दौरान, पेट्रोल-डीज़ल पर 9 बार उत्पाद कर (एक्साइज़ ड्यूटी) बढ़ाया गया। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच पेट्रोल पर ये बढ़ोतरी 11 रुपये 77 पैसे और डीज़ल पर 13 रुपये 47 पैसे थे पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की केंद्र सरकार को मिलने वाला राजस्व लगभग तीन गुना हो गया।





जून 2017 में मोदी सरकार ने एक नया फार्मूला लागू किया, कहा गया कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में रोज बदलाव होते रहते हैं इसलिए इसे आधार बनाकर पेट्रोल-डीजल के दाम बदले जाएंगे। इससे पहले कच्चे तेल के 15 दिनों के औसत मूल्यों के आधार पर पेट्रोल डीजल के दाम तय किये जाते थे लेकिन इस निर्णय के बाद से यह कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव गिरेगा तो कीमत घटेगी ओर बढ़ेगा तो बढ़ेगी।

लेकिन पिछले 4 सालों में मोदी सरकार का अवलोकन करें तो साफ हो जाएगा कि देश की जनता को एक बार भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरी हुई कीमत से उपलब्ध लाभ लेने नहीं दिया गया बल्कि हर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर खजाना भरा गया। कोरोना काल की शुरुआत में तो अंतराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमत 14.25 डॉलर प्रति बैरल गिर गयी तब भी किसी तरह का लाभ भारत की जनता को नहीं दिया गया।

ऐसा नहीं है कि केन्द्र की सरकार चाहे तो महंगाई कम नहीं कर सकती, लेकिन सरकार की नीयत महंगाई के प्रति साफ नहीं दिखती है, बस चुनाव ही चुनाव दिखता है अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनाव संपन्न हुए तब तक पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़े लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए भाव बढ़ा दिये गये। मोदी जी चाहें तो पेट्रोल डीजल के दाम आधे से भी कम कर सकते है, क्योंकि उन्होंने 2015 से कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी से खरबों रु. कमाया है और सरकारी खजाना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा कर भरा जाता है।

आसमान छू रही महंगाई ने आम लोगों का जीना दुभर कर रखा है। खासकर मध्यवर्गीय परिवार परेशान है क्योंकि इन्हें सरकार की तरफ से कुछ भी मुफ्त नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जियों, दालों और अन्य रोजमर्रा की चीजों के दामों में आग लगी हुई है। बहुत से लोगों के सामने संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सरकारों को रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं के दाम जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि देश के हर वर्ग को महंगाई से राहत मिले। ▪



आ जा आजमगढ़

जिस तरह से नाम बदलाव का दौर चल रहा है। इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, फैजाबाद का अयोध्या। कल को शायद आजमगढ़ भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए। आजमगढ़ कब तक रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है इसीलिए आईये और आजमगढ़ को जानिए। अलीगढ़, नौगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, रामगढ़ की तरह एक नाम है आजमगढ़।

▪ **विक्रमजीत**



इतिहास में आजमगढ़ -

प्रारम्भिक दिनों में यहाँ कृषक, पशुपालकों के साथ जनजातियां होने पर वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार देवव्रत के अनुसार गंगा और घाघरा के मध्य बसा यह भौगोलिक क्षेत्र चरवाहों और कृषि के बेहद अनुकूल क्षेत्र रहा होगा। पशुपालन के लिए बड़ें-बड़ें मैदानों और खेती के लिए उपजाऊ जमीन, उनके बसने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थियां रही होगी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आज भी आजमगढ़ एवं आसपास की अधिकांश जनसंख्या खेतिहर, पशुपालन व्यवसाय और पशुओं से जुड़ें व्यवसायी लोंगों की है।

मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में स्थानीय जागीरदार आजम खां के नाम से आजमगढ़ की स्थापना हुई है। अर्थात आजमगढ़ जिसके नामकरण के पीछे तत्कालीन शासक के सम्मान में हुआ और बाद में एक भौगोलिक इकाई के रूप में आजमगढ़ अस्तित्व में आ गया। यहां आजमगढ़ मंडल में आधुनिक मउ जनपद भी शामिल है जिसका इतिहास आजमगढ़ से ही बनता है।

1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन का आजमगढ़ में बहुत ही व्यापक प्रभाव रहा। आजमगढ़ में 1942 का यह आंदोलन जनसामान्य का आंदोलन था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक जातियों खासकर अहीरों ने अपने परम्परागत हथियार लाठी और भाला के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तत्कालीन जिलाधिकारी राबर्ट निब्लेट ने आजमगढ़ में विद्रोह की स्थिति का सजीव वर्णन किया है निबलेट ने लिखा है कि हाथ में लाठी और भाला लिए दस हजार से ज्यादा की इस भीड़ की हलचल को देखकर ऐसा लगता था जैसे सरपत का कोई समूचा जंगल चलायमान हो। यहाँ सरपत लाठी के अर्थों में प्रयोग किया गया है। लाठी की पहचान अहीरों से स्थापित की जाती है। मुहावरों में कहा जाता है- अहीर की लाठी।

15 नवम्बर 1994 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आजमगढ़, मऊँ और बलिया को मिलाकर 14 वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का निर्माण किया गया और आजमगढ़ जिले में मंडल मुख्यालय बनाया गया।

आजमगढ़ की बसावट-

वर्तमान आजमगढ़ जिला मुख्यालय तमसा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तमसा नदी तीनो तरफ से आजमगढ़ जिला मुख्यालय को घेरे हुए है। मुख्यालय के चारो तरफ के गांव अहीरों और कोइरी जैसी अन्य कृषक जातियों के हैं। हरखूपुर, शाहगढ़, बुदैठा, गेरुआरा, तमौली, मत्तीबाग, अहोपट्टी,पगरा, मंचोभा, इशहापुर, मनचोभा, हरिहरपुर, अजामपुर चकिया गांवों से जिला मुख्यालय घिरा हुआ है, ये गाँव भैंस पालकजाति बाहुल्य हैं जो प्रो. कांचा इलैया की इस मान्यता को बल प्रदान करता है कि किसी बस्ती या शहर की बसावट पशुपालकों द्वारा की जाती है। बसावट वहां वहां हुई जहां नदियां या जल स्रोत थे क्यों कि जल पशुओं के लिए भी उतना ही जरुरी है जितना की मनुष्यों के लिए। गांव के बसावट को के पीछे भी इन्ही चरवाहों का बड़ा योगदान रहा, जहाँ जहाँ से भैसें गुजरी वहां वहां बस्तियां बसती चली गयी।

आजमगढ़ जिले के ऐसे मोहल्ले और कस्बे जो इसके देशज और स्वाभाविक बसावट की ओर इशारा करते हैं, जिले के गंज लगे मोहल्ले/ कस्बों में कलीनगंज, जुनेदगंज, जहानागंज, महाराजगंज, दीदारगंज, बिलरियागंज, लालगंज प्रमुख हैं। जिले के पुर लगे मुहल्लों/ कस्बों/ गांवों में खुदादादपुर चक्रपानपुर, मुबारकपुर, गोपालपुर, हाजीपुर, फूलपुर, रामापुर, तहबरपुर जैसे अनेंक नाम हैं। उसी तरह से जिले में निजामाबाद, शाहबाबाद जैसे अनेंक नाम हैं जिनके अन्त में बाद लगा

है।

विदेशों में आजमगढ़ – वर्तमान समय में आजमगढ़ जिले की एक बड़ी जनसंख्या विदेशों में रहती है, एक जमाने में जब मोबाइल संचार भारत में प्रचलित नहीं था तब आजमगढ़ जिले के सरायमीर से बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय फोन काल किया जाता था, कस्बे के रूप में भारत में सबसे अधिक काल सरायमीर से की जाती थी।

आजमगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में मुंबई, सूरत, दिल्ली, लुधियान- पंजाब में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आजमगढ़ मुंबई के लिए गोदान और दिल्ली के लिए कैफियत एक्सप्रेस चलती है, जिनपर यात्रा के लिए महीनों पहले टिकट लेना पड़ता है।

फिल्मों में आजमगढ़ – कई बॉलीवुड फिल्मों में आजमगढ़ की बहुत ही निगेटिव छवि दिखाई गई है। चूंकि आजमगढ़ की एक बड़ी जनसंख्या मुम्बई में रहती है, यह बालीबुड फिल्मो में आजमगढ़ की दबंग छवि ने शुरुआत में लोगों को बहुत रिझाती थी लेकिन बाद में यह नकारात्मक असर दिखाने लगी। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के अधिकतर खलनायकों के नाम यादव अथवा मुस्लिम जाति का हुआ करते हैं। फिल्मों द्वारा गढ़ी गयी



इस छवि का प्रभाव यह है कि आजमगढ़ के लोगों को न्यायालय से अपराधी घोषित किए जाने से पहले ही मीडिया द्वारा अपराधी करार दे दिया जाता है।

आजमगढ़ का प्रमुख उद्योग -

मुबारकपुर का साड़ी/ हथकरघा उद्योग - मुबारकपुर जिला मुख्यालय के उत्तर-पूर्व से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इस जगह को कासिमाबाद के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद इस जगह का पुर्ननिर्माण करवाया गया। इस जगह को दुबारा राजा मुबारक ने बनवाया था। यह जगह बनारसी साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन बनारसी साड़ियों का निर्यात पूरे विश्व में होता है। साड़ी का यहाँ के मुख्य पहनावे में शामिल होना ही इस उद्योग के विकसित होने का एक मुख्य कारण है। आजमगढ़ में रेशमी साड़ी निर्मित करने का उद्योग लघु उद्योग के रूप में विकसित है। यहाँ की साड़ियों में "पल्लू" पर रेशमी कढ़ाई का साड़ी के शेष भाग के साथ बेहतरीन समायोजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह उद्योग फैला हुआ है। इस उद्योग की विशेषता यह है कि इसके साथ कई अन्य उद्योग भी पल्लवित होते रहते हैं। छपाई, डिजाइन, परिवहन व विपणन आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी सीधे तौर पर इस उद्योग के साथ जुड़ें हुए हैं।



आजमगढ़ के पूर्व सांसद -
वर्ष सांसद पार्टी
1952 कलिका राय कांग्रेस
1962 राम हरख यादव कांग्रेस
1967 चंद्रजीत यादव कांग्रेस
1971 चंद्रजीत यादव कांग्रेस
1977 रामनरेश यादव भारतीय लोकदल
1978 मोहसिना किदवई कांग्रेस (उपचुनाव)
1980 चंद्रजीत यादव जनता पार्टी सेक्युलर
1985 संतोष सिंह कांग्रेस
1989 राम कृष्ण यादव बसपा
1991 चंद्रजीत यादव जनता पार्टी
1996 रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी
1998 अकबर अहमद डंपी बसपा
1999 रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी
2004 रमाकांत यादव बसपा
2008 अकबर अहमद डंपी बसपा (उपचुनाव)
2009 रमाकांत यादव भाजपा
2014 मुलायम सिंह यादव समाजवादी

निजामाबाद के काली मिटटी के बरतन-

जनपद के निजामाबाद क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की काली मिट्टी से इन बर्तनों का निर्माण किया जाता है। लगभग 200 से अधिक कारीगर यहाँ इन बर्तनों का निर्माण करते हैं। इन बर्तनों में गुलदस्ते व अन्य बर्तन भी शामिल हैं। सजावट व दैनिक उपयोग के लिए भी इस कला की बहुत माँग होती है। निजामाबाद में निर्मित सुंदर बर्तन विश्व प्रसिद्ध हैं यहाँ के कुम्हार चाय के बर्तन, चीनी के बर्तन व अन्य कलात्मक बर्तनों का निर्माण करते हैं।

आजमगढ़ की लाल भरुआ मिर्च— आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र में बड़ें पैमाने पर उत्पादन होता है इसका उपयोग अचार बनाने के लिए होता है यहाँ से यह अन्य प्रदेशों और खाड़ी देशों में भेजी जाती है लाल भरुआ मिर्च की एशिया की सबसे बड़ी मंडी अजामगढ़ जिले की पूलपुर की मिर्चा मंडी है। ■

@ +91 9450591835





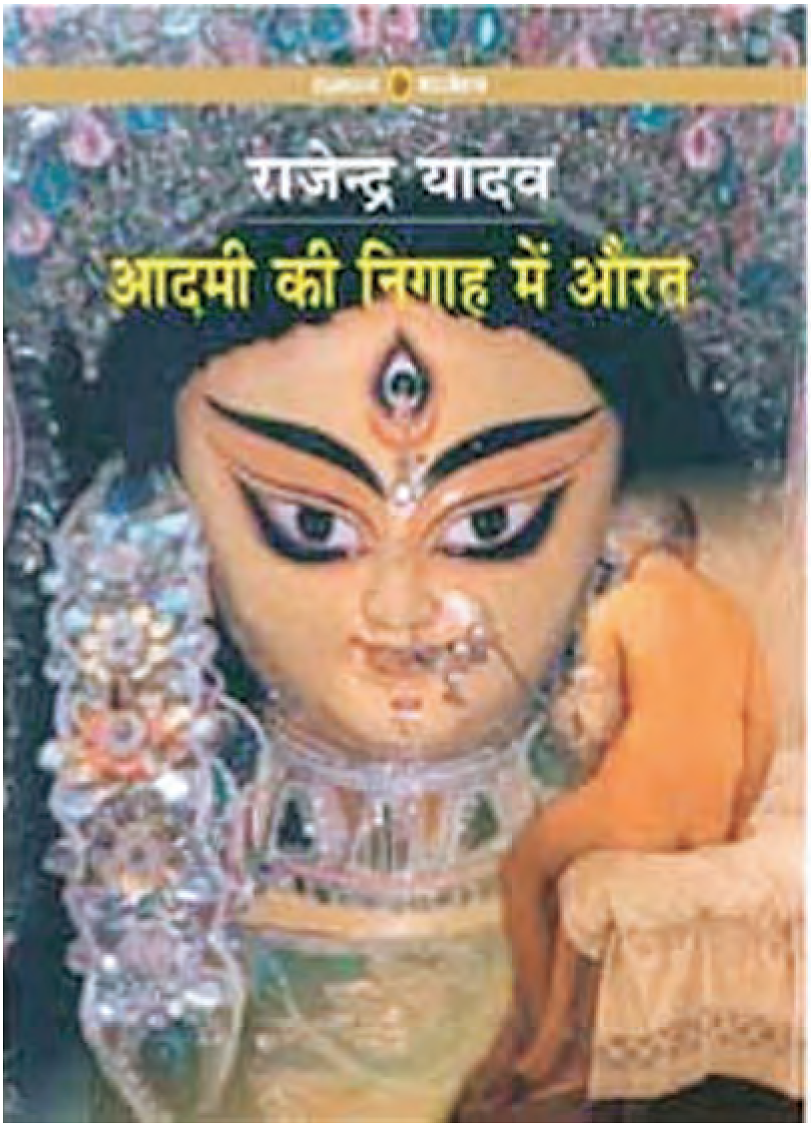


स्मृति में शेष...
राजेन्द्र यादव एवं ओमप्रकाश वाल्मीकि

हिंदी साहित्य जगत में अपने लेखों और विचारों से खलबली मचने वाले दो महान व्यक्ति त्व राजेंद्र यादव और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने वर्ष 2013 में दुनिया को अलविदा कह दिया। 28 अक्त ूबर को राजेंद्र यादव और 17 सितम्बर को ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्मृति दिवस है। बसावन इंडिया इन महान सचेतकों को इनके स्मृति दिवस पर नमन कर रही है। इनके बारे में लिखने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन बसावन इंडिया इनके स्मृति दिवस पर इनको याद करते हुए इनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियों को आपसे सांझा कर रही है।

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

हिन्दी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर राजेंद्र यादव हिन्दी साहित्य की दुनिया के एक मजबूत स्तंभ थे। राजेंद्र यादव का नाम चोटी के लेखकों में शुमार था। वह मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका हंस का 1986 से संपादन करते रहे थे, जो हिन्दी की सर्वाधिक चर्चित साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है और इसके माध्यम से हिन्दी के नए लेखकों की एक नई पीढ़ी भी सामने आई और इस पत्रिका ने दलित विर्मश और स्त्री विर्मश को भी स्थापित किये थे। उन्हें मौजूदा दौर में हिन्दी साहित्य की कई प्रतिभाओं को सामने लाने का श्रेय जाता है। हिन्दी साहित्य जगत में उपन्यास, कहानी, कविता और आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं में राजेंद्र जी एक जैसी पकड़ रखते थे। यशस्वी कथाकार-सम्पादक राजेन्द्र यादव की इस किताब में स्त्रियों की मुक्ति की राह में मौजूद अनगिनत गुत्थियों पर लिखे लेखों में अनेक कोणों से विचार किया गया है। बीते लगभग चार दशकों में विभिन्न विचारोत्तेजक मसलों पर स्त्रियों के पक्ष में दी गई दलीलों के साथ-साथ इन लेखों में बार-बार उन पेचीदगियों की तरफ भी इशारा किया गया है, जिन पर हमारा रूढ़िबद्ध मन सोचना नहीं चाहता। कहते हैं कि दुनिया अगर चार पहाड़ों के बोझ तले पिस रही है तो औरतों पर पाँच पहाड़ों का बोझ है–पाँचवा पहाड़ पुरुष सत्तात्मक विधान का है। आज जबकि पुनरुत्थानवादी शक्तियाँ भारतीय समाज में बड़े ठस्से के साथ घूम रही हैं, यह छिपा नहीं रह गया है कि धर्म और नैतिकता की आड़ में सबसे ज़्यादा अत्याचार औरतों पर ही हो रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए कि धर्म के तालिबान हर युग में औरत की नाकेबन्दी करते आए हैं। इस किताब में दो खंड हैं। पहला खंड स्त्री-दासता के रगो-रेशे उधेड़ते हुए उसके ऐतिहासिक



सन्दर्भों की पड़ताल करता है जबकि दूसरे खंड में स्त्री विषयक चुनिन्दा रचनात्मक साहित्य को परत-दर-परत टटोलते हुए उसकी सीमाओं और सम्भावनाओं पर उँगली रखने का जोखिम लिया गया है। राजेंद्र यादव की पुस्तक आदमी की निगाह में औरत की कुछ पंक्तियाँ–

.....भारतीय समाज में न नारी का अपना कोई व्यक्तित्व रहा है, न जाति। वह ऐसा रत्न है जिसे कहीं से भी उठाया जा सकता है और जिसके पास है उसी की सम्पत्ति है। वे व्यक्ति नहीं, 'चीज हैं जिन्हें लूटा, छीना और नष्ट किया जा सकता है, खरीदा और बेचा जा सकता है। सारा इतिहास इन उदाहरणों से भरा है कि किस आक्रमण में कितने हाथी-घोड़े, हीरे-जवाहरात और औरतें लूटी गईं। जिस सामन्त या सम्राट के पास जितने अधिक दास और औरतें थीं वह उतना ही बड़ा चक्रवर्ती माना गया। सन् 47 के देश विभाजन में भी कितनी औरतें छीन ली गईं-या लौटा दी गईं- यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है। आज भी जब दुश्मन को नीचा दिखाना या सबक सिखाना हो तो उसकी बहन-बेटियाँ ही उठाई या भ्रष्ट की जाती हैं। दलितों का दम तोड़ने के लिए उनकी औरतों पर बलात्कार तो सबसे अचूक नुस्खा है। रक्त-शुद्धता या ब्लू-ब्लड वाली सामन्ती शेखियों के मुँह पर यह भी एक बड़ा तमाचा रहा है कि हर काल में हर जाति और धर्म की औरतें एक-दूसरे के यहाँ हस्तान्तरित हुई हैं और फिर भी वे इस मुगालते को पाले रखते थे कि नस्ल में माँ का तो कुछ होता ही नहीं, जोभी खून बच्चे में होता है वह सिर्फ बाप का होता है। मानो माँ एक जड़ डिब्बा है जहाँ बाप का वीर्य पलता है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि

ओमप्रकाश वाल्मीकि का जन्म एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। जूठन हिंदी भाषा के लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा है। पुस्तक दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है और साथ ही भारतीय जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों को भी उठाती है। पुस्तक केवल एक व्यक्ति विशेष की अपनी आत्मकथा होने के अतिरिक्त उस समुदाय विशेष की त्रासद कथा भी वर्णित करती है। यह आत्मकथा वर्ण-जाति व्यवस्था के क्रूर एवं वीभत्स चेहरे को परत-दर-परत उजागर करती है। लेखक प्रति अन्य लोगों का नजरिया क्या है, उसका वर्णन वह इन शब्दों में करता है- 'अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते-बिल्ली, गाय-भैंस को छूना बुरा नहीं था; लेकिन चूहड़े का स्पर्श हो जाए, तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंको.'

ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' हिंदी साहित्य जगत और समाज में एक विस्फोट की तरह सामने आई। इसने हिंदी साहित्य में यथार्थ के नाम पर परोसे जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय समाज के उन सारे आवरण को तार-तार कर दिया, जिनकी ओट में महान भारतीय संस्कृति का गुणगान किया जाता था। 'जूठन' में द्रोणाचार्य के विद्रूप चेहरा आप देख सकते हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन की कुछ पंक्तियाँ हम आपसे साझा कर रहे हैं-

...एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, "क्यानाम है बे तेरा?"

"ओमप्रकाश," मैंने डरते-डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी।

"चूहड़े का है?" हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला।

"जी।"

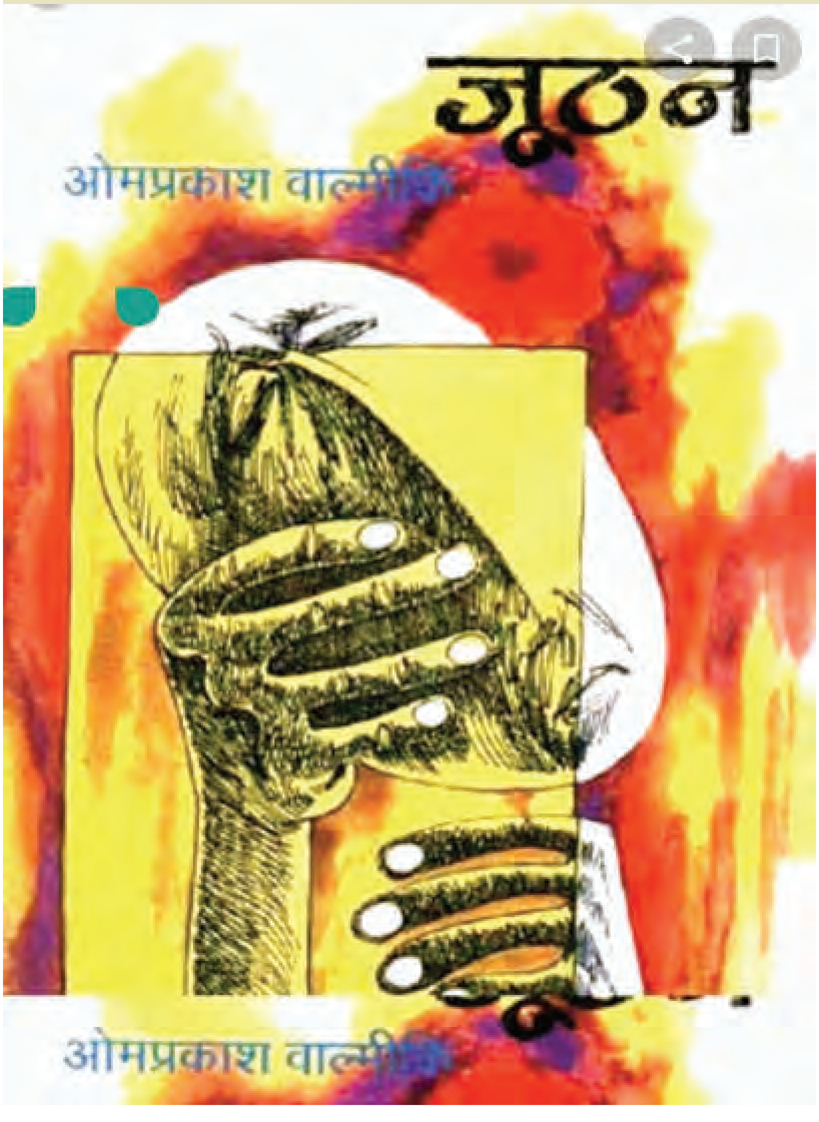
"ठीक है"वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जाऔर टहनियाँ तोड़के झाड़ू बणा ले। पत्तों वाली झाडू बणाना और पूरे स्कूलकू ऐसा चमका दे जैसा सीसा। तेरा तो यो खानदानी काम है। जा फटाफट लग जा काम पे।

हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे, बरामदे साफ कर दिए तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी

ओमप्रकाश वाल्मीकि की स्मृति में...

चमार समझ जाते थे,
चीलों और बाजों को उड़ते देख,
कौवों और गिद्धों को उड़ते देख,
जरूर कोई न कोई मरा जानवर पड़ा होगा।
जरूर न जरूर कोई जानवर गाड़ा गया होगा।
भोजन के लिए दौड़ पड़ते थे,
घर लाते और बिना मसाले के खाते थे।
इस जाति व्यवस्था ने इंसान नही समझा,
कमाल की बात है और ताज्जुब भी,
सेक्स करने के लिए लिंगानुपात के कारण
उच्च जातियों का प्रलोभन देकर दलित
लड़कियों से शादी करना।
दलित धनी लड़की / दलित आईएएस
अधिकारी से परिण्य सूत्र बंधने में वो इंसान
हो जाती है।
तब ब्राह्मण का लिंग या उच्च जाति का लिंग
इतना सेकुलर क्यों हो जाता है?
क्या सचमुच जाति व्यवस्था हमें इंसान
समझती है?
या किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा है।

डॉ. विक्रम
असिस्टेंट प्रोफैसर
इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय



साफ कर दे।"

लंबा-चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने सेमेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अँट गया था। मुँह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा।

तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर मेंभाइयों का मैं लाड़ला था। दूसरे दिन स्कूल पहुँचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम परलगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल सेकक्षा में बैठ जाऊँगा।तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बादउनकी दहाड़ सुनाई पड़ी, "अबे, ओ चूहड़े के, मादरमम कहाँ घुस गया।

अपनी माँ..."

उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के नेचिल्लाकर कहा,"मास्साब, वो बैट्ठा है कोणे में।"

हेडमास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी उँगलियों कादबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका। चीखकर बोले, "जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू" नहीं तो गांड में मिर्ची डालके स्कूल से बाहर काढ़ (निकाल) दूंगा।" ▪



बिलासपुरी...

▪ सिओक

यहाँ से मजदूर परिवार के साथ, समूह में और कभी-कभी आधी बस्ती पलायन कर जाती है। अपना खेती, घर जानवर को छोड़ कर दुःख के साथ बड़ी समस्या लेकर महानगरों की ओर पलायन करते है। इन मजदूरों को बाहर से आकार सरदार/ जमादार(दलाल) काम दिलाने के लिए ले जाते है। सरदार जमादार का मजदूरों के ऊपर अपना कमीशन होता है। इस तरह मालिक को भी सस्ते दरों में मजदूर मिल जाते है। महिलाओं और पुरुषों की दिहाड़ी में काफी अंतर होता है हर शहरों में अलग-अगल दिहाड़ी दी जाती है। यूपी के ईंट भट्ठों पर पूरा परिवार मिलकर एक दिन में 4 से 5 सौ रुपये कमा लेता है।

अधिकतर मजदूर ईट भट्ठा पर काम करने जाते हैं। वहाँ उन से बंधुवा मजदूर की तरह काम कराया जाता है। मालिक के चाहने पर ही छुट्टी मिलता अन्यथा नहीं चाहे मजदूरों के परिवार में बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों न आ जाये अगर छुट्टी देगा भी तो उनका कुछ पैसा रोक लेगा ताकि काम करने के लिए उनके पास ही दोबारा आए। मजदूर तो जमादार के माध्यम से काम करने जाते है और मजदूरी का भुगतान भी जमादार करता है। आर्थिक शोषण के साथ साथ महिला कामगारों का कार्य स्थलों पर दैहिक शोषण होता है, कभी मालिकों द्वारा, कभी सरदारों/ जमादारों द्वारा तो कभी बिचौलियों द्वारा। इनकी स्थिति बधुआ मजदूर की तरह हो जाती है। हाल ही में श्रीनगर के अनंतनाग जिले में मजदूर ईंट भट्ठा में काम करने गये है उनका जमादार मालिक से पैसा लेकर फरार हो गया, जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ के मजदूर है अब मालिक उनसे मार पीट डरा

बिलासपुर के आसपास से पलायन करने वाले मजदूर वर्ग को उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में बिलासपुरी नाम से जाना जाता है। गांवों में रहने वाले मजदूर रोजगार की तलाश में बेबस होकर पलायन करते हैं। इतनी सारी रोजगार के योजनाओं के बाद भी पलायन हो रहा है।





धमका कर काम करने के लिए मजबूर करते है।

पलायन की वजह...

पलायन पलायन करनेवाले ज्यादातर लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर और छोटे किसान है। इनके पास खरीफ की फसल के बाद कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर गांव में रोजगार मिल भी जाता है तो दिहाड़ी कम होती है जिससे परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। किसी वर्ष बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया या फसल बर्बाद हो गई तो पूरी की पूरी बस्ती को पलायन के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। आजीविका चलाने के लिए ऐसे समय में कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। पलायन करते है तो बस्ती वीरान हो जाती है केवल बुजुर्ग ही घरों में दिखाई देते।

पलायन करने का बहुत सारी वजहें हैं बेटी का विवाह का खर्च जैसी सामाजिक बुराई, मूलभूत आवश्यक्ता रोटी कपड़ा और मकान, साहूकार का कर्ज, खेती के खाद बीज उपलब्ध, जमा पूंजी, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक रीति-रिवाज, दशगात्र जैसे अनेक कारण है।

शहरों में होने वाली समस्या ...

मजदूर जमादार के सम्पर्क में जाते है और कड़ी मेहनत करते है समय में मजदूरी का भुगतान न हो पैसे में बेईमानी कर दिया ऐसा डर बना रहता है। कभी -कभी काम नहीं मिल पाता है उन्हें सुविधा हमेशा कम ही मिलता है ऊपर से स्थानीय निवासियों का डर हमेशा बना रहा है।

मजदूर बताते है कि अपने गांव से बेहतर जगह कोई नहीं है शहर में काम के पैसे तो मिलते है लेकिन इतने दबाव में काम करते है मत पूछो हर आदमी हमारे ऊपर अपना गुस्सा उतार कर चला जाता है गांव में पैसा कम है पर वहाँ खुशी सुकून अपनापन है जो यहां चाह कर भी नहीं मिल पाता।

भाषा समझने में समस्या आती है काम कराने वाले सर लोग तो टूटी फूटी हमारी हिंदी समझ लेते है पर स्थानी लोग नहीं समझते समान खरीदने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

पलायन का समय....
गांवों में खरीफ की फसल की बुवाई और रोपाई के बाद असाड़ सावन माह में बड़ी संख्या में पलायन करते है कुछ मजदूर खरीफ की फसल के कटाई के बाद शहरों की ओर पलायन करते है पहले मजदूर कुछ गिने चुने शहरों में काम करने जाते थे अब तो मजदूर देश के कोने-कोने जा रहे है जहाँ उनको थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाए। अक्सर जो मजदूर शहरों में पलायन करके काम करते है वो लोग अपने गांव को याद करते हुए कहते है अपन गाँव मा जाबो, तहा तरिया में नहाबो (जब अपने गांव जाएंगे तो तालाब में नहाएंगे) कहते हुए अत्यंत आनंदित होते है।

स्वास्थ्य खराब हीने पर इलाज कराने की समस्या अगर कोई सदस्य ज्यादा बीमार पड़ गया तो इलाज कराने में बड़ी परेशानी होती है यहाँ इलाज बहुत महंगा है और सही इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु का भय बना रहता है। ▪

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

☐ **वार्षिक ₹ 300/-** ☐ **2 वर्ष ₹ 500/-** ☐ **5 वर्ष ₹ 1000/-**

☐ **10 वर्ष ₹ 5000/-** ☐ **आजीवन ₹ 10,000/-**

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40414082862
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम

मो.:

हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

सांस्कृतिक भीम क्रांति 14 अक्टूबर 1956



वैसे तो वैश्विक इतिहास में फ्रांस की क्रांति को खासा महत्व है और भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सत्ता को खत्म करने के लिए किए गए संघर्ष को भी क्रांति कहा जाता है। यह दोनों संघर्ष/ क्रांति सत्ता परिवर्तन के लिए किए गया है पर 14 अक्टूबर 1956 को हुई सांस्कृतिक क्रांति इन दोनों क्रांति से अलग है और वैश्विक इतिहास में वह जगह नहीं मिल पाई है जिसकी यह क्रांति हकदार है।

▪ आकाश संजय खोब्रागड़े

यह क्रांति भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसकी जड़े प्राचीन भारत के चार्वाक, बौद्ध, सम्राट अशोक से होते हुए संत कबीर, रविदास, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर तक आती है। इस क्रांति की खासियत का अंदाजा आप इसी पर लगा सकते है की क्रांति करने वाले समाज ने अपनी 2500 साल की सांस्कृतिक और सामाजिक गुलामगिरी को एक ही झटके में तोड़ दी वह भी बिना किसी हिंसा के। यह क्रांति इतनी व्यापक है की आज 65 वर्षो बाद भी हर वर्ष इसी दिन पर लाखों के संख्या में लोग दीक्षा भूमि नागपुर (14 अक्टूबर 1956 को जहाँ क्रांति हुई थी) आते है और समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रेरणा लेते है। इसी क्रांति को विश्व धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के रूप में जानते और मनाते है। इसी क्रांति के बाद भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत हुई है जिसकी अगुवाई डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी इसलिए इस लेख का नाम सांस्कृतिक भीम क्रांति 14 अक्टूबर 1956 रखा गया है।

हर क्रांति की तरह इस क्रांति में भी समय और जगह की अपनी एक विशेषता है पर सांस्कृतिक क्रांति होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी होता है। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर इसे समझते हुए दशहरा को चुना जिसे बौद्ध धम्म में अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है जिसकी तारीख वर्ष 1956 में 14 अक्टूबर को थी। इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तन दिन दशहरे को मनाया जाता है। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने उस दिन अपने लाखों अनुयाइयों के साथ मिलकर बौद्ध धम्म स्वीकार लिया, साथ ही बौद्ध धम्म के पालन के लिए बाईस प्रतिज्ञा भी दी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भारत भूमि पर बौद्ध धम्म का इतना व्यापक पुनर्जागरण इसी क्रांति के बाद हुआ। यह क्रांति सीधे-सीधे भारत के हाशिये पर धकेले गए लोगों द्वारा लाई गई थी जिस से वह अपना आत्मसम्मान और सामाजिक बराबरी हासिल कर सके। जिस जगह पर डॉ. बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी आज उस जगह पर दीक्षाभूमि नामक बौद्ध स्तूप है।

हर वर्ष दशहरे के दिन लाखों लोग भारत के अलग-अलग कोने से दीक्षाभूमि आते है बाईस प्रतिज्ञा का पाठ करते है साथ ही स्तूप में जाकर बौद्ध और डॉ. बाबा साहब अंबेडकर को अभिवादन करते है। लोगों के स्वागत के नगरवासियों तथा सरकारी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर व्यवस्था की जाती है। खाना, पीने के लिए पानी, सोने के लिए जगह, साथ ही स्टेशन से स्तूप और स्तूप से नागपुर के अन्य बौद्ध स्थल लाने और ले जाने तक की व्यवस्था इस में शामिल होती है यह सब व्यवस्था मुफ्त और धम्म सेवा के रूप में की जाती है। खाने और पीने के पानी की व्यवस्था मध्य रात्री तक शुरु रहती है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए दीक्षाभूमि को फूलों और लाइटिंग से सजाया जाता है और स्तूप में अपने वालों की संख्या देखते हुए स्तूप चौबीस घंटों के लिए खोल दिया जाता है। इतना ही नहीं स्तूप के परिसर में और रास्तो पर विभिन स्टॉल होते है जिसमें मुख्यतः पुस्तक के स्टॉल होते है, जो दिखलाता है जिस समाज को शिक्षा वर्जित थी आज वह समाज इस क्रांति के बाद शिक्षित होकर सामने आया है। अन्य स्टालों पर मूर्तिया, प्रबोधन भाषण, सामाजिक जागरूकता के गीत, सरकारी सेवाओं के विज्ञापन आदि होते है। इसी दौरान कई बाबा साहब को मानने वाले संगठन सफाई कार्यक्रम, स्वस्थ जांच







शिविर, शिक्षा संबंधी जानकारी और दीक्षाभूमि व्यवस्था का देखभाल करते है। यह जब लोग एक दूसरे से मिलते है तब जय भीम बोल कर अभिवादन करते है और डॉ. बाबा साहब अंबेडकर द्वारा की गई क्रांति को याद करते है।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष कोरोना के चलते धम्मचक्र प्रवर्तन दिन नहीं मनाया जा सका। 2020 में जब कोरोना अपने चरम पर था उस वर्ष पूर्ण रूप से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन रोक दिया गया थी जिस पर लोगों ने भी सरकार का साथ दिया था। इस वर्ष 2021 में भी इसी तरह की रोक थी पर लोगों के आग्रह और नागपुर के पालक मंत्री डॉ. नितिन राऊत के मध्यस्थता के बाद कोरोना नियमों पालन करते हुए लोगों स्तूप में जाने की अनुमति दे दी गई। लोगों के स्वागत में हर वर्ष की तरह दीक्षाभूमि की सजाया गया था पर किसी भी तरह का स्टॉल या खाने की सुविधा इस बार नहीं की गई थी, पर पीने का पानी महाराष्ट्र बिजली विभाग द्वारा दिया गया था। इस वर्ष लोगों के जनसैलाब में भारी कमी दर्ज की गई। लोगों की कमी के दों कारण है पहला की कोरोना के चलते दीक्षाभूमि का खुलना तय नहीं था, दूसरा दीक्षाभूमि खोलने का आदेश देरी से आया जिस वजह से देश के अन्य भागों से आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। फिर भी अभिवादन करने वालों की संख्या लाखों में दर्ज की गई, जिस वजह से दीक्षाभूमि को रातभर खुला रखने का आदेश दिया गया साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी लोगों को नियंत्रण करने के लिए तैनात किया गया था। नागपुर शहर और महाराष्ट्र राज्य के साथ अन्य राज्य के लोगों दीक्षाभूमि पर मौजूद थे। छोटे स्तर पर समाज प्रबोधन हो रहे थे, भिक्षु और भिक्षुणी बौद्ध धम्म का महत्व आए हुए लोगों को बता रहे थे। संगठन जैसे समता सैनिक दल सरकारी सुरक्षा बल के साथ मिलकर लोगों स्तूप में जाने के लिए मदद कर रहे थे और कोरोना के नियमों का पालन करा रहे थे।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष कई सांस्कृतिक कार्यक्रम दीक्षाभूमि पर नहीं हो सके फिर भी लोगों के अपने अपने तरह से बौद्ध और बाबा साहब को अभिवादन कर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन दीक्षाभूमि में मनाया और नव चेतना के साथ वापस लौट गए। ▪

@ +91 9021687231

पुस्तक समीक्षा - मैं एक कार सेवक था

▪ प्रस्तुति - डॉ. कालूलाल कुलमी



भंवर मेघवंशी की आत्मकथा, अब इसका अनुवाद अँग्रेजी तमिल में हो चुका हैं। एक आत्मकथा किसी समाज के दस्तावेज की तरह ही है। एक दौर था जब आत्मकथा लिखने का दौर था और लिखना एक चुनौती हुआ करता था, आज भी है। अपने सच को लिखना साहस का काम हैं यह हर कोई नहीं कर सकता। असल में सच कहना ही साहस का काम है और जो इसको कहता हैं उसके सामने खतरे तो होते ही हैं। जब हम खुद से ही झूठ कहते हैं तब जमाने से सच कहना जाहिर हैं खुद को खोलना भी है और बोलना भी। हम कई बार अपने को अलग तरह से अभिव्यक्त करने के लिए अलग-अलग विधा में ले जाते हैं। कलाकार के लिए वो लाजिमी है। भंवर जी एक साधारण जीवन के साथ अपने को अपने सम्मान के लायक करते हुए, उम्मीद करते कि लोग उनको उनके हिस्से का सम्मान दे। और ये उम्मीद करना कोई गलत नहीं हैं। एक नागरिक को उसका हक मिलना ही चाहिए, अगर उसको वो हक नहीं मिलता हैं तो वो उसके लिए लड़ता भी है और उसको हासिल भी करता हैं। भँवर जी की आत्मकथा अपने होने का हक लेने की कहानी नहीं, समय और समाज का कटु यथार्थ हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी ने मोटी किताब लिखी तो वो महान ही हैं- किताब का सत्य और उसका प्रभाव किताब की उम्र तय करते हैं। गांधी की आत्मकथा और बच्चन की आत्मकथा। गांधी की आत्मकथा एक छोटी- सी किताब और हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में हैं। लेकिन कौन किसको कितना पढ़ता हैं किसका कितना प्रभाव हैं सब जानते हैं। सच कहना और सच को लपेटना दोनों दो बाते हैं।

उनकी रवीन्द्रनाथ का उपन्यास गोरा का नायक गोरा भी सब कुछ के साथ लड़ रहा था। अपनी जान अपना सब कुर्बान कर रहा था लेकिन जब उसकी नस्ल का पता चला तो उसका सब कुछ भर से गिर गया और वो अपने से समझा कि ये क्या हुआ। भंवर जी भी आरएसएस में अपनी जान लगा कर लड़ रहे थे। जीना- मरना सब उसी के साथ था लेकिन इस सब के बीच उनकी जाति आई और सब कुछ जैसे एका-एक गिर गया। मतलब ये किस मर्ज की दवा हैं। एक आदमी दलित हैं, बस यही कारण हैं कि आप उसको खारिज करते हैं उसको अपने उस साँचे में नहीं रख पाते- फिर आप उससे क्या उम्मीद करते हैं वो आपको अपना कैसे मान लेगा।

"इतना ही नहीं बल्कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, मन होता मातृ भूमि तुझको और भी कुछ दे जैसे राष्ट्र प्रेम के गीत और बातें मन को अभिभूत कर देती थी। हर दिन होली दिवाली-सा माहौल होता था मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि हम शाखा में जाने वाले लोग ही पक्के राष्ट्रभक्त हैं। जो शाखा में नहीं जाते वे देशद्रोही हैं।" पृ-51

जो इस भाव तक समर्पित था उस विचार के प्रति वो एक दिन उसको छोड़ कर अपने रास्ते पर चल पड़ा और फिर उसके जीवन में संकट ही संकट खड़े हो गए। जो कल तक उसके थे आज एकदम विरोधी हो गए। मारने पर उतारू हो गए और हर तरह से इसको अपराधी बना दिया। लेकिन भंवर जी के साथ कुछ अपने कुछ खास अपने थे और वो लड़ते रहे। और प्रण किया कि लड़ते रहेंगे ताउम्र। फिर क्या था वो अपने रास्ते पर चल पड़े और आज भी जारी है कारवां चल रहा और और लोग जुड़ रहे हैं।

इस देश में एक खास तरह का विमर्श चला- और ये कोई नयी बात नहीं हैं। जो लोग अपने महान होने की कहानियाँ सुनाते नहीं थकते उनके पीछे का आधार देखने पर वो किसी ने किसी बड़ें आदमी के कोई न कोई लगते हैं। उनके पीछे कोई न कोई हैं। कुछ नहीं है तो बड़ी जाति के तो है ही। दिलीप मण्डल की बातों से असहमति हो सकती हैं लेकिन उनके तर्क और उनका विमर्श नया नहीं हैं वो वही विमर्श हैं जिस पर भारत के प्रगतिशील बात करने से डरते रहे हैं। और उसका ही परिणाम है कि आज वो खुद ही अपने विमर्श में फंस गए हैं। जब आप जाति में मानते हैं तो फिर बात करने में क्या हर्ज हैं। जब आपका समाज जातिवादी हैं तो उसको स्वीकारने में क्या हर्ज हैं। टिवीटर जातिवादी हैं तो इसको कहने में क्या डर हैं। आजतक भी विवि में आज कौन लोग हैं और उनकी खुद कि क्या योग्यता हैं? क्या इस पर बात नहीं होनी थी। पर नहीं कि केवल अपने लोगों को भरा और बाकी को कर दिया बाहर। यही हाल सब तरफ हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि बात होनी चाहिए और खुलकर। तभी संभव हैं रास्ता। भंवर जी कि आत्मकथा उसकी भी ताकीद करती हैं।

इटालियन विचारक ग्रामशी जिनके जीवन

के आखिरी दस साल जेल में बीते लेकिन वो जिस विचार को लेकर आते हैं वो मार्क्स से आगे का हैं। वो जिस ऑर्गेनिक बुद्धि जीवी की बात करते हैं वो उस जमीन से आता हैं तो वो समाज के सच को समझता हैं। वो हर सवाल का जवाब भी खुद ही है। भंवर जी भी कुछ वही हैं। इस देश में जितनी विविधता हैं उसको देखकर आप अलग-अलग जाति के अलग-अलग अनुभव के लोग ज्ञान की दुनियाँ में आते हैं तो आपको समझने का मौका मिलता हैं। जब हम एक है जमीन से आते हैं तो वो हमें अलग अनुभव नहीं दे सकता और यही कारण हैं कि हम समाधान नहीं तरफ नहीं अधिक उलझन में जा रहे हैं। न्यू इंडिया में सब कुछ साफ हैं। इस किताब में संघ का विचार क्या हैं ये खुद उसका जानने वाला बता रहा हैं। परत-दर-परत हर बात के विचार हैं पिछले 40 बरस की कहानी हैं। पिछले 40 बरसों में इस देश के जीवन में क्या घटा इससे आप परिचित हो तो और भी आसान है इस किताब औ इसके कथन को समझना।

जिंदगी के खेल बहुत निराले हैं, जीवन इतना सरल होता नहीं जितना दिखलाई पड़ता हैं। कई उतार चढ़ाव जीवन में आए। कभी-कभी लगा कि सिर्फ हम नाम-मात्र के जीवन-साथी हैं, लेकिन ढाई आखर का ताना-बाना सदैव बचा रहा। दांपत्य और यारी दोस्ती कि एक अदबौद्ध कहानी जिसे मैंने लौट आओ कणों में पिरोया है। वह प्रेम, प्रेम से विवाह और विवाह के बाद के प्रेम की अकथ कथा हैं जो बताती है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी से भी मुलाकात हो सकती हैं और कोई भी कभी भी बिछुड़ सकता हैं, कोई नहीं जानता, मगर मैं अपने दिल कि दुनियाँ के अनायास पाये वरदानों से सदैव उल्लसित रहा हूँ और मेरी दिली तमन्ना यह है कि एक दिन सम्पूर्ण जीवन ही प्रेम में परिवर्तित हो जाए और उस दिन आने तक लव जेहाद जारी रहे तो क्या बुराई है। पृ -177

जीवन का सार हो या अनुभव- जिसकी जो सोच होती है वो उसी तरफ जाता हैं। भंवर जी की सोच है कि जीवन को बेहतर बनाया जाए, अनवरत। गांधी के विचार अनुभव सोच और बाकी सब पढ़ना सीखना और इस तरह अपने को एक अच्छी दुनियाँ के लिए तैयार करना- यही मामूली सा कथन हैं। अंबेडकर के जीवन को समझना और कैसे संवाद को संभव करना- संवाद ही रास्ते खोलता हैं वही आपको समझ देता हैं वही आपके लिए समझ का माध्यम बनता हैं। किसी के प्रति दुराग्रह न पालते हुए उसके बारे में सही से जानना ही अपने को सही रास्ते पर ले जाना हैं।

आत्मकथा पढ़ते हुए बहुत से विचार आते हैं। बहुत बार लगता हैं ऐसा भी होता है फिर लगता हैं ऐसा कैसे हो सकता हैं। लेकिन भंवर जी जिस सलीके से जीवन से सीखते हैं और निरंतर अपने को रचते हैं वो साहस का काम हैं और वो उनके लिए कठिन था और है लेकिन भंवर जी ने उसको अपनी सहजता और मित्रों के आसरे और परिवार के आसरे किया -और उनको आवाज दी जो बोलने से डरते थे। उनको उनके होने का पता दिया। मुझे लगता हैं कि हरेक के विचार उसके जीवन बोध और जीवन के कठिन डगर से आते हैं। कौन कितना सीखता है ये उस पर निर्भर करता हैं। कोई प्रतिशोध का रास्ता चुनता है तो कोई प्रतिरोध का। कोई रचता हैं तो कोई तोड़ता हैं। उतर आधुनिकता अगर नेरेटिव तोड़ने की बात करती हैं और अपने तरीके से उसको रचने की बात करती हैं तो उसका अर्थ किसी के पहलू से न लिया जाए। उसके अनेंक आयाम हैं। सत्य के कई पक्ष होते हैं उसकी किसी एक ही साँचे में नहीं ढाला जा सकता। उसके हर पहलू को जाना जाना जरूरी हैं। ▪

@ +91 9340964101

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे प्रथम एवं द्वितीय अंक में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।



कुचिया के प्रेम की पराकाष्ठा, मां से मिलने को **मन बहुत हुड़कता है** के साथ ही 'मेरे लेखे मर गई' सुनकर विश्वास नहीं करती और बड़की भाभी पर शक करती है। परन्तु भाई बिना कुछ कहे जाने को खड़ा हो जाता है तो उसका स्वाभिमान उग्रता के चरम पर पहुंच जाता है और जिसके लिए मन हुड़क रहा था,उसकी दिशा से भी नफरत हो जाती है।

जितनी बार पढ़ें, भावना का ज्वार बढ़ता ही जाता है। कहानीकार को बधाई।

जीडी यादव

ओमगायत्री नगर इलाहाबाद

बसावन इंडिया गागर में सागर जैसा प्रयास है, उम्मीद करता हूं कि यह समाज में समाज को समझने,समझाने का काम करके बुद्धिजीवी समाज के य|ों का पुंज बनेगी बजाय व्यक्तिगत उपलब्धि के।

एड. कुलदीप सिंह

बुलन्दशहर

सामाजिक न्याय का विमर्श बढना चाहिए। सामाजिक न्याय की सीमाएं, दायरे के साथ-साथ अवधारणाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए मंच के माध्यम से।

उदयपाल सिंह यादव

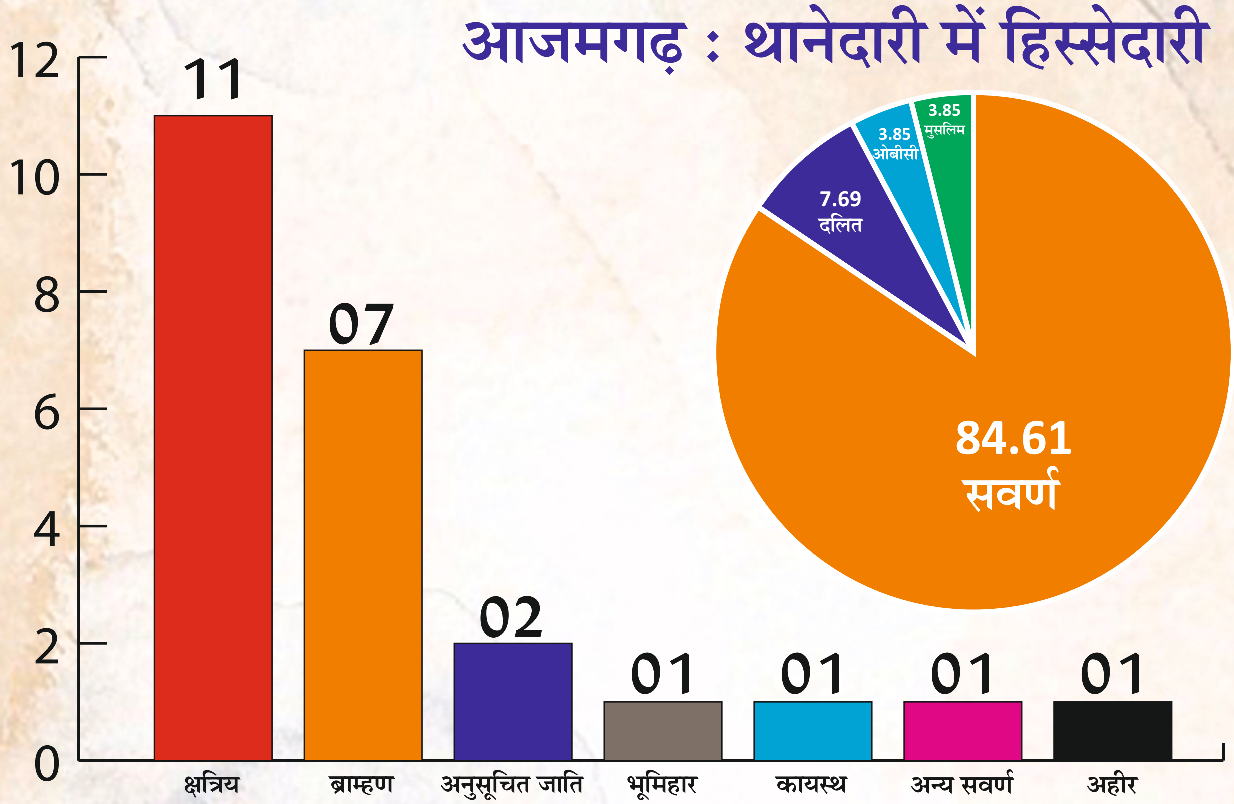
नगर पालिका अध्यक्ष कम्पिल

बसावन इंडिया एक अलग कलेवर की पत्रिका लगी। खासकर वास्तविक भारतीय समाज की आवाज लग रही है। मुद्दो का चयन और लेखकगण इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। कागज और प्रिंटिंग भी आकर्षक है।

सरस्वती की भूमि से निकली पत्रिका निःसन्देह दबे कुचले पिछड़ों के मुद्दो की ओर न सिर्फ ध्यानाकर्षक करेगी बल्कि आवाज साबित होगी।

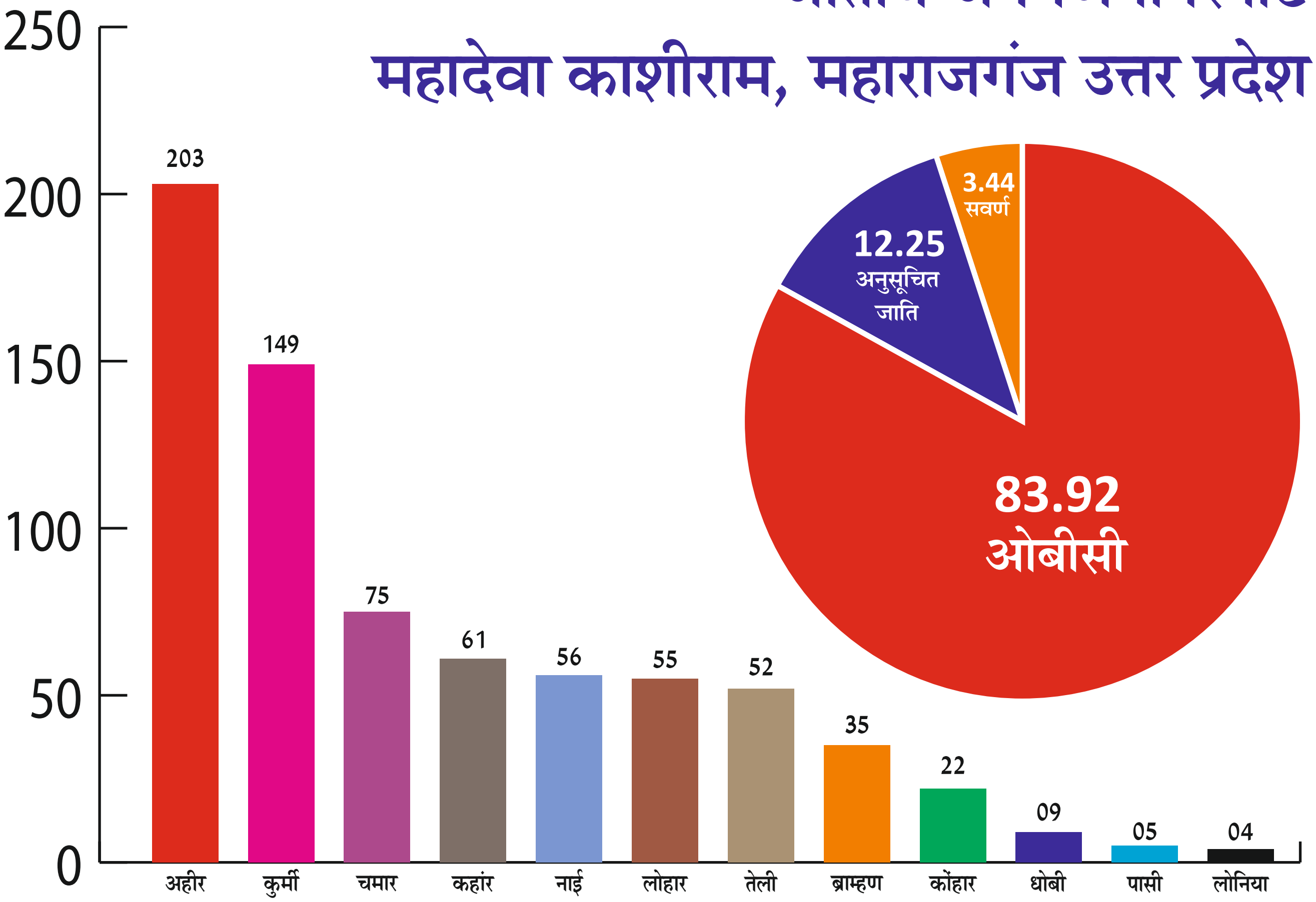
टीटू प्रधान

सिंघावली अहीर, बागपत



प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 16 पढ़ें।

जातीय जनगणना रिपोर्ट
महादेवा काशीराम, महाराजगंज उत्तर प्रदेश



प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 17 पढ़ें।